हिमाचल की प्रगति एवं संस्कृति का दर्पण

गिरिराज

साप्ताहिक

Mkd i;thdj.k la[;k ,p-ih-@42@,l-,e-,y- 2009 lekpkj i= iathdj.k la- vkj-,u-vkbZ- 32195@78

o"kZ 32 vad 8 f'keyk] 25 uoEcj&1 fnlEcj] 2009 gj c/kokj dks çdkf'kr eY; ,d izfr 3-00 #i;s okf"kZd 140 #i;s vkthou 1500 #i;s website : himachalpr.gov.in/giriraj.asp

घर बैठे गिरिराज पाइये

गिरिराज का आजीवन ग्राहक बनने के लिए सदस्यता शुल्क 1500 **रुपये** बैंक ड्राफ्ट या मनिआर्डर के माध्यम से **निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, शिमला**-2 व वार्षिक सदस्य बनने के लिए सदस्यता शुल्क 140 **रुपये, सम्पादक, गिरिराज साप्ताहिक, शिमला**-171005 के नाम से भेजें।

ir; efiu dkM ,o njHkk"k ;k ekckby u- fy[kuk u Hkwysa

इस अंक में

कृषि/बागबानी/विकास...	5
सर्व शिक्षा अभियान	6-7
साहित्य...	8
महिला/बाल जगत/स्वास्थ्य ...	9
पहाड़ी पृष्ठ	10

विज्ञापन प ष्ठ अतिरिक्त

इजराइल द्वारा जल प्रबन्धन एवं अक्षय ऊर्जा में सहयोग की पेशकश

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के दल द्वारा इज़राइल में सिंचाई एवं पॉलीहाउस तकनीक के अध्ययन के दौरान दिखाई गई रुचि के दृष्टिगत इज़राइल सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ जल प्रबन्धन एवं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का प्रस्ताव रखा है। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों ने इन दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में इज़राइल के साथ पहले ही समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित कर रखे हैं।

जिन नौ इज़राइली कम्पनियों द्वारा

मुख्य मंत्री का इजराइल दौरा

गत दिवस हिमाचल प्रदेश के दल के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया गया था, ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ स्प्रिंकलर एवं टपक सिंचाई पर समन्वय स्थापित करने में रुचि दिखाई।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल, ने इज़राइली कृषि एवं सिंचाई गतिविधियों के अध्ययन से संबंधित क्षेत्र का दौरा किया तथा वहां अपनाई जा रही व्यवस्था एवं तकनीक की जानकारी प्राप्त की। हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव सिंचाई श्री नरेन्द्र चौहान, सचिव कृषि एवं बागबानी, श्री राम सुभग सिंह और निदेशक पर्यटन श्री अरुण शर्मा भी इस अवसर पर उनके साथ थे।

मुख्य मंत्री तथा दल ने वहां पॉलीहाउस एवं सिंचाई व्यवस्था का अवलोकन किया तथा सेब के बागीचों को भी देखा। इज़राइल 3000 से 3500 फुट की ऊंचाई पर गुणात्मक सेब का उत्पादन कर रहा है और वहां सेब की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 40 से 45 टन है। टपक सिंचाई से भूमि के उपजाऊपन को बढ़ावा तथा धुन्ध रोकने के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग इज़राइल की विशेषता है।

मुख्य मंत्री इज़राइल में सहकारिता आधार पर की जा रही खेती से प्रभावित हुए। यहां दो समुदायों, किब्बूमज़ तथा मोशाव द्वारा सहकारिता आधार पर 75 से 80 प्रतिशत उत्पादन किया जा रहा है। उत्पाद का विपणन भी सहकारिता आधार पर ही किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री एवं दल ने ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग गृहों, कोल्ड स्टोरेज़ एवं फैक्टरियां जो सिंचाई के उपकरणों का निर्माण कर रही हैं, का दौरा भी किया।

(शेष पृष्ठ 11 पर)

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल इजराइल के तेल अवीव में प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए

- कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा
- इजराइल द्वारा प्रदेश के विकास में गहरी रुचि
- कृषि-बागबानी की आधुनिक तकनीकों को प्रदेश में अपनाया जाएगा
- कुल्लू दशहरे में इजराइली सांस्कृतिक दल को आमंत्रण

निःशुल्क एंबुलैंस सेवा शीघ्र

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में फरवरी, 2010 से निःशुल्क एंबुलैंस सेवा आरंभ करने का निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 100 एंबुलैंस तैनात की जाएंगी जो रोगियों के लिए चिन्हित स्थानों पर उपलब्ध होंगी।

यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव बिंदल ने गत दिनों शिमला में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मरीजों के पास 20 से 45 मिनट के मध्य एंबुलैंस पहुंचेगी तथा इस सुविधा के लिए टोल फ्री नं. 108 उपलब्ध होगा जिसके लिए सरकार ने आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि यह सेवा एक निजी कंपनी अंजना इंडस्ट्रीज एंबुलैंस आयशर यूनियन के सहयोग से चलाई जाएगी जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे। उन्होंने बताया कि इस सुविधा पर सालाना लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इन एंबुलैंसों को अत्याधुनिक काल सेंटर से जोड़ा जाएगा तथा किसी दुर्घटना या गंभीर रोगी के लिए काल सेंटर पर काल करके एंबुलैंस मांगी जा सकेगी। इन एंबुलैंसों में प्राथमिक उपचार की सभी सुविधाएं जैसे ऑक्सीजन आदि के साथ-साथ प्रशिक्षित स्टॉफ भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय जिलों को छोड़ कर यह सुविधा शेष सभी जिलों में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कंपनी के साथ अनुबंध करने से पहले सरकार ने इसका सर्वेक्षण करवाया है। यह एंबुलैंस उपग्रह संचार प्रणाली (जीपीआरएस) से जुड़ी होगी तथा सरकार इस योजना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत धनराशि प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने निजी क्षेत्र में इस सेवा को आरंभ करने का निर्णय लिया है तथा इससे स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी।

जैविक उर्वरक उत्पादन में सहयोग करेगा जापान

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मौसम की अनिश्चितता, वैश्विक उष्मीकरण तथा घटते भू-जल स्तर के दृष्टिगत जल के समुचित उपयोग एवं सिंचाई उपयोगी तकनीक अपनाने की आवश्यकता है, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में कृषि गतिविधियों को और प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तथा इससे जहां समुद्रों का जलस्तर बढ़ेगा, वहीं पहाड़ों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है। मुख्य मंत्री ने गत दिनों शिमला में अंतरराष्ट्रीय न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी।

प्रो. धूमल ने कहा कि विश्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना के कार्यान्वयन में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जो प्रदेश के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय संरक्षण की दिशा में कारगर कदम है। उन्होंने कहा कि जापान की अंतरराष्ट्रीय सहकारी एजेंसी ने राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जैविक उर्वरक के उत्पादन में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया है।

(शेष पृष्ठ 11 पर)

मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना से सकल घरेलू आय में नौ प्रतिशत की वृद्धि

विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश को देश का कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने में सहायता करेगा। यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमालयन पारिस्थितिकीय के सभी बाहरी व आंतरिक स्रोतों के संरक्षण की सभी सम्भावनाओं को तलाश रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विश्व बैंक की पहल स्वागत योग्य है जिससे हिमाचल प्रदेश को भविष्य में कार्बन न्यूट्रल राज्य के रूप में उभरने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं जिसके तहत हरे वृक्षों के कटान व प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबन्ध, विशेष पौधरोपण अभियान, प्रदूषण न फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों को लगाने की स्वीकृति प्रदान करना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना हुई है।

प्रो. धूमल ने कहा कि मिड हिमालयन जलागम विकास परियोजना से राज्य के पारिस्थितिकीय सन्तुलन को बनाए रखने में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लागू हो जाने के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं तथा इससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लागू होने से घरेलू आय में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पांच प्रतिशत परिवार ए.पी.एल श्रेणी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत सूक्ष्म व छोटी सिंचाई योजनाओं के निर्माण से 1,724 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई क्षेत्र के अधीन लाया जा चुका है, जिससे 20,795 परिवार लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई क्षेत्र में भी 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि परियोजना क्षेत्र में फसल (शेष पृष्ठ 11 पर)

- ✱ परियोजना क्षेत्र में फसल उत्पादन में 26 प्रतिशत व सब्जी उत्पादन में 43 प्रतिशत वृद्धि
- ✱ पारंपरिक फसलों में 6 प्रतिशत तथा फल उत्पादन में 11 प्रतिशत वृद्धि

हि.प्र. विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने महिला साक्षरता के लिए प्रदेश को सराहा

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में गत दिनों 17वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव, जो विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हैं, ने समारोह की अध्यक्षता की। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि थे। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान भी इस अवसर पर उपस्थित थे। दीक्षांत समारोह में 415 डिग्रियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें एक डी. लिट्, 187 पी.एच.डी. और 227 पदक एवं पुरस्कार शामिल हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने इस अवसर पर पुरस्कार जीतने वालों में लड़कों से आगे रही लड़कियों की सराहना की और कहा कि हिमाचल प्रदेश, देश के उन गिने-चुने राज्यों में शामिल है, जहां महिला साक्षरता दर अधिक है। श्री मुखर्जी ने कहा कि देश-विदेश में शिक्षित युवाओं के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं है लेकिन अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए उन्हें देश हित को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अपने ज्ञान के बल पर युवा ही इस देश को आगे ले जाने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह एक ऐसा अवसर है, जब डिग्री धारक युवाओं को अपने ज्ञान को मानव कल्याण में लगाने की शपथ लेनी चाहिए। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एक सशक्त आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है और देश को अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं की जरूरत है। आज के समय में युवा देश को महत्त्वपूर्ण दिशा प्रदान कर सकते हैं।

श्री मुखर्जी ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा कमाई का साधन बनता जा रहा है जो कि शिक्षा का एक सतही लक्ष्य है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि सही मायनों में शिक्षित होने का अर्थ है एक अच्छा इंसान और बेहतर नागरिक बनना। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को (शेष पृष्ठ 11 पर)

युवाओं के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी—राज्यपाल

सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प

मुख्य सचिव श्रीमती आशा स्वरूप ने श्रमिक वर्ग की प्रदेश के विकास में सराहना करते हुए आग्रह किया है कि वे इसमें बढ़चढ़ कर अपना सहयोग दे।

हिमाचल प्रदेश भारतीय मजदूर संघ की गत दिनों आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्रीमती स्वरुप ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है तथा उनके हितों को सुरक्षित बनाया जा रहा है, जिससे वे समाज में सुविधाजनक एवं सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस वर्ग की मांगों के प्रति हमेशा ही गंभीर रही है तथा समय पर उनकी जायज मांगों को पूरा करती रही है।

श्रीमती स्वरूप ने कहा कि श्रमिकों के लंबित मामलों को तीन माह के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2009 तक 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके दिहाड़ीदारों को विभागों द्वारा उपलब्ध रिक्त पदों पर नियमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रियाशील पदों को प्रत्येक वर्ष भरा जाएगा, जिससे विभागों का कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार को उन श्रमिकों का विस्तृश्त ब्योरा दिया जाए, जो निर्धारित अवधि पूरी करने के पश्चात् भी नियमित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सैद्धांतिक तौर पर लिए गए निर्णयों के अनुसार वर्कचार्ज तथा अनुबंध कर्मियों को भी प्राथमिकता पर नियमित किया जाएगा।

मजूदर संघ की मांगों को प्रमुखता दी जायेगी-मुख्य सचिव

उन्होंने कहा कि मजदूर संघ की मांगों को प्राथमिकता पर लिया जाएगा तथा जांच के पश्चात् इन्हें मंत्रिमंडल की बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से महिला सामाजिक कल्याण बोर्ड की क्राफ्ट टीचरों के लंबित वेतनमान पर गौर करने के लिए कहा ताकि उन्हें वेतन अविलम्ब जारी किया जा सके। उन्होंने कहा कि करूणामूलक आधार पर 425 मामलों को हाल ही में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है, जबकि नियुक्ति के शेष मामलों पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र ठाकुर ने आग्रह किया कि राज्य में श्रम कानूनों को सही परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाए, जिससे श्रमिक वर्ग लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को श्रमिक वर्गों के कल्याणार्थ तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण एवं प्रदेश के विकास के लिए उनकी मांगों को प्राथमिकता पर निपटाए जाने की आवश्यकता है। सचिव श्रम एवं रोजगार श्री अनिल खाची ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष तथा भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मेहनत से मिला सफलता का मुकाम

परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसी वाक्य को चरितार्थ किया है टकोली के नरोतम ने। सीमित संसाधनों के बावजूद जिला मण्डी के टकोली गांव के नरोतम राम ने आज सफलता के जिस मुकाम को हासिल किया है वह निश्चय ही किसी भी व्यक्ति के लिए एक सपने से कम नहीं है। नरोतम राम बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखता है। परिवार में आय के सीमित संसाधन थे। नरोतम के पिता भीमू राम घर में ही खड्डी का कार्य करके परिवार की रोजी-रोटी कमाते थे। पिता का अनुसरण करते हुए नरोत ने भी खड्डी व्यवसाय को अपनाया तथा फिर कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा और आज देश के सर्वश्रेष्ठ हस्तशिल्पियों में उनका नाम शामिल है। उन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ट्राईसम योजना के तहत प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्होंने बाद में क्षेत्र के लड़के-लड़कियों को प्रशिक्षित किया।

इसी तरह जिला उद्योग केन्द्र मण्डी द्वारा ग्रामीण दस्तकार योजना के तहत भी उन्हें बीपीएल परिवारों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा दिया गया। अब तक वह मण्डी तथा कुल्लू जिला के 200 लड़के-लड़कियों को हथकरघा उत्पादों के बारे में प्रशिक्षित कर चुके हैं। उन्हें भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने वर्ष 2006 के लिए पूरे भारत वर्ष के कुशल हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा बुनकरों में सर्वश्रेष्ठ बुनकर का राष्ट्रीय अवार्ड देकर सम्मानित किया जो नरोतम के साथ-साथ प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने वर्ष 2006 के लिए पूरे भारत वर्ष के कुशल हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा बुनकरों में नरोतम को सर्वश्रेष्ठ बुनकर का राष्ट्रीय अवार्ड देकर सम्मानित किया जो प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

इसके साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के कुशल हस्तशिल्पियों तथा हथकरघा बुनकरों का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड वर्ष 2007 के लिए भी नरोतम को मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है।

नरोतम ने टकोली में हिमालयन वीवरज नाम से सहकारी सभा चला रखी है जहां पर हस्त निर्मित उत्पादों को तैयार किया जा रहा है। इस सोसायटी में वर्तमान में 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं। सोसायटी का वार्षिक कारोबार 30-35 लाख रुपये तक पहुंच गया है। नरोतम अभी कुल्लू, किन्नौरी तथा अन्य हिमाचली शॉल तथा अन्य हथकरघा उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ देश के दूसरे राज्यों की जरूरत के अनुसार उत्पाद तैयार कर रहे हैं। वह विदेशों में भी वहां की जरूरत के मुताबिक उत्पाद तैयार करके भेज रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचली हथकरघा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उन्हें जर्मनी भी भेजा गया।

हिमाचल प्रदेश तथा हस्त शिल्प एवं हथकरघा निगम जिला मण्डी इकाई के प्रभारी तथा बिक्री अधिकारी लक्ष्मी नंद शर्मा के अनुसार जिला मण्डी के सभी बुनकरों को उनके उत्पाद बेचने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनियां तथा बिक्री केन्द्र लगाये जा रहे हैं। प्रत्येक प्रदर्शनी में पांच से सात स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया जा रहा है ताकि बिचौलियों का काम समाप्त करके बुनकर व्यवसाय से जुड़े लोगों को उनके उत्पाद का सही दाम मिल सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के विकास आयुक्त हथकरघा, कपड़ा मंत्रालय द्वारा जिला मण्डी के लिए तीन वर्षों की एक एकीकृत हथकरघा विकास परियोजना चलाई गई है जिसके तहत जिला में बुनकर व्यवसाय से जुड़े 27 स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा गया है तथा इन्हें निगम द्वारा जहां कच्चा माल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

–के.सी. चौहान

सशक्तिकरण की राह पर हिमाचल की महिलाएं

राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सामजिक-आर्थिक दशा सुधारने और उन्हें संबल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

ऐसी ही एक योजना है मुख्य मंत्री कन्या दान योजना। इस योजना के तहत ऐसी बेसहारा महिलाओं और लड़कियों को 11001 रुपये प्रति महिला की दर से अनुदान दिया जाता है जिनके माता-पिता या संरक्षकों की वार्षिक आय 15,000 रुपये से कम हो। वर्ष 2008-09 में इस योजना के तहत 116.10 लाख रुपये खर्च कर 1056 महिलाओं व लड़कियों को लाभान्वित किया गया।

मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली नि:सहाय महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 18,000 रुपये से कम हो, को उनके बच्चों के पालन-पोषण के लिए 2000 रुपये प्रति बच्चे की दर पर आर्थिक सहायता उपलबध करवाई जाती है। यह सहायता दो बच्चों के लिए 14 वर्ष तक दी जाती है। वर्ष 2008-09 में इस योजना के अन्तर्गत 13060 बच्चों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने पर 107.28 लाख रुपये व्यय किए गए।

लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने और उनके लिए आय के स्रोत उत्पन्न करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा बालिका समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए चलाई जा रही है। योजना के तहत जन्म के पश्चात बालिका के नाम बैंक या डाकघर में 500 रुपये जमा करवाए जाते हैं और 18 वर्ष की होने पर लड़की इन पैसों को निकाल सकती है। योजना के तहत स्कूल जाने पर इन लड़कियों को दसवीं कक्षा तक छात्रवृति भी दी जाती है। वर्ष 2008-09 में इस योजना में 13409 लड़कियों को लाभान्वित करने पर 75 लाख रुपये व्यय किए गए।

राज्य में घटता लिंगानुपात चिन्ता का विषय है और राज्य सरकार इस दिशा में गम्भीर प्रयास कर रही है। सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे कन्या भ्रूण हत्या से सम्बन्धित सभी कानूनों का कड़ाई से पालन करवाएं। लिंग जांच करने वाली सभी क्लीनिकों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है और राज्य, ज़िला एवं ग्राम स्तर पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

लड़कियों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुधारने, पढ़ाई-लिखाई और व्यावसायिक कौशल के लिए एक और महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है किशोरी शक्ति योजना। इसके तहत वर्ष 2008-09 में 95944 किशोरियों को पूर्ण पोषाहार, 2851 को कौशल विकास प्रशिक्षण, 143987 को ऑयरन फॉलिक ऐसिड गोलियां, 173030 को पोषाहर एवं स्वास्थ्य शिक्षा और 64 लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग दी गई। 87,387 लड़कियों का हेमोग्लोबिन जांचा गया। योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 47 लाख रुपये व्यय किए गए। राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 25 हजार रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। वर्ष 2008-09 में ऐसे 86 दम्पतियों को लाभान्वित करने पर 21.50 लाख रुपये व्यय किए गए।

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य की उन्नति और आत्मनिर्भरता के पथ पर महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाओं का तीव्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित बनाया जा सके।

निराश्रित एवं असहाय महिलाओं को आसरा प्रदान करने के लिए शिमला जिला के मशोबरा में नारी सेवा सदन चलाया जा रहा है जहां महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। प्रत्येक महिला को 10 हजार रूपये का पुनर्वास भत्ता भी दिया जाता है। वर्ष 2008-09 में इस योजना के तहत 42 लाख रुपये व्यय किए गए। राज्य सरकार ऐसी विधवाओं एवं परित्यक्त महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 6000 रुपये से कम है, को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के रूप में 330 रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। ऐसी 64074 महिलाओं को वर्ष 2008-09 में 2500 लाख रुपये व्यय कर लाभान्वित किया गया।

सही मायनों में महिला सशक्तिकरण तभी सम्भव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ और स्वतंत्र हों। राज्य सरकार ने बेरोज़गार कन्याओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के कई अवसर सरुजित करने की घोषणा की है। इस दिशा में महिला स्वयं सहायता समूह उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 24329 महिला स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं जिनकी वार्षिक आय 77 करोड़ रुपये से अधिक है।

राज्य में वर्तमान में 14 कामकाजी महिला छात्रावास भी चलाए जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और कार्यस्थल पर उनका शोषण रोकने के उद्देश्य से सभी सरकारी, गैर सरकारी, बोर्डों और निगम कार्यालयों में महिला शिकायत निवारण समितियों का गठन किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय में एक जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई है।

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य की उन्नति और आत्मनिर्भरता के पथ पर महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित है।

सूजसवि

चम्बा जिला में समेकित बाल विकास कार्यक्रम

●सुखदेव

जिला चम्बा में बाल विकास परियोजना, समेकित बाल सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 1448 आंगनबाड़ियों के माध्यम से शिशुओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषाहार, पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच तथा टीकाकरण जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में जिला के 7 खण्डों चम्बा, चुवाड़ी, मैहला, सलूणी, तीसा, भरमौर तथा पांगी में 6 माह से 6 वर्ष तक के 50071 बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार व पूर्व शिक्षा जैसी सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं ताकि वे प्रारम्भिक शिक्षा के लिये परिपक्व हो सकें। चालू वर्ष में 4148 गर्भवती व धात्री माताओं को पूरक पोषाहार व स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान की गई। पूर्व शाला के तहत 3 से 6 वर्ष आयु के 19055 बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिक्षित किया जा रहा है। जिला के विकास खण्डों में बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में पैदा हुई दो बालिकाओं के नाम 500 रुपये की राशि प्रति बालिका के नाम से जमा करवाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत जिला में 698 बालिकाओं जिनमें 182 अनुसूचित जाति, 177 अनुसूचित जनजाति, 10 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 329 अन्य वर्ग की बालिकाओं के नाम 349000 रुपये जमा किये गये।

किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत लड़कियों को स्वरोजगार अपनाने व उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए जिला में 455 लड़कियों को दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस योजना के तहत 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक विकास के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषाहार स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, व्यावसायिक दक्षता बढ़ाना, स्वच्छता तथा बच्चों की देखभाल बारे शिक्षित करना, सामाजिक गतिविधियों बारे जागरूक किया जाना तथा आर्थिक निर्भरता के लिए उत्पादक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया गया है जिस पर इस योजना के तहत 172600 रुपये की राशि व्यय की गई।

चालू वित्त वर्ष में जिला में 660 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिनमें चम्बा में 103, चुवाड़ी में 214, मैहला में 137, सलूणी में 26, तीसा में 144, भरमौर में 36 समूह शामिल किये गये हैं जिनमें से कुल बचत 5101453 रुपये हैं तथा ग्रामीण स्तर पर आर्थिक कार्यों के लिए बैंकों से 5082510 रुपये का ऋण लिया गया है। इन आर्थिक गतिविधियों में दूध उत्पादन आटा चक्की, आचार निर्माण वस्त्र निर्माण तथा अन्य कार्य शामिल हैं।

कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों का अहम योगदान–मुख्य मंत्री

कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जापान सरकार द्वारा जैविक खाद परियोजना के लिए 270 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों हमीरपुर ज़िला के भोरंज उपमण्डल के दूरदराज गांव बलोह में हिमकोफेड द्वारा आयोजित 56 वीं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वर्कर्स के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान दी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि लक्षित नीतियों और कार्यक्रमों के कारण सहकारी अभियान तेजी पकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों को किसानों को पुरानी पारम्परिक कृषि प्रणाली छोड़कर आर्थिकी बढ़ाने वाली नकदी फसलें एवं हर्बल पौधों को लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस कार्य में सहकारी बैंक एवं सहकारी समितियों को किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने किसानों से 353 करोड़ की पंडित दीन दयाल किसान बागबान समृद्धि एवं 300 करोड़ रुपये की दुग्ध गंगा योजना से लाभान्वित होने का आग्रह किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। प्रो. धूमल ने कहा कि राज्य की लगभग 4500 सहकारी समितियों में 13.66 लाख सदस्य हैं। 2477 सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें दो सहकारी बैंक, 375 ऋण एवं बचत सहकारी समितियां तथा 2092 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां है शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों द्वार चालू वित्त वर्ष के दौरान 375.68 करोड़ रुपये के कृषि व गैर-कृषि ऋण आबंटित किए गए हैं उन्होंने कहा कि ऋण राहत योजना-2008 के तहत 1,27,211 गरीब किसानों को 211.80 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि जनजातीय ज़िले किन्नौर एवं लाहौल स्पिति में समन्वित सहकारी विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिस पर क्रमशः 433.41 करोड़ और 414. 15 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आन्दोलन सिरमौर, बिलासपुर व हमीरपुर ज़िला में भी पुनर्जीवित किया जाएगा।

मुख्य मंत्री ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के 120 वें

बहुमूल्य योगदान के लिए सहकारी सभा समितियां सम्मानित

जन्म दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की जिसे पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रो. धूमल ने राजकीय उच्च पाठशाला बलोह के शौचालय निर्माण के लिए 50 हजार रुपये, दीवार निर्माण के लिए 1 लाख रुपये तथा मैदान निर्माण के लिए 2 लाख रुपये, पेयजल आपूर्ति के लिए 2 लाख रुपये, स्कूल के पुराने भवन की मुरम्मत के लिए 3 लाख रुपये स्वीकृत किए तथा पांच नए कमरों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। मुख्य मंत्री ने पूर्व विधायक श्री कर्म सिंह ठाकुर को उत्कृष्ट सहकार के लिए सम्मानित किया। इसके अलावा श्री रजनीश राणा और श्री रमेश कुमार को सहकारी प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा व कांगड़ा ज़िला के गरली में डिप्लोमा कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2007-08 के लिए तलाई ग्राम सेवा सहकारी सभा समिति को प्रथम स्थान तथा बिलासपुर ज़िला के दधोल ग्राम सेवा सहकारी सभा पडियालग ने द्वितीय स्थान व बाधर एग्रीकल्चर सेवा सहकारी सभा हरोली, ऊना को कोऑपरेटिव आन्दोलन को मज़बूती प्रदान करने के लिए तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। उन्होंने बलोह सहकारी सभा समिति को सहकारी क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए ट्रॉफी प्रदान की।

इससे पूर्व मुख्य मंत्री ने इफको द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन को क्षेत्र सहकारों को समर्पित किया।

शिक्षा मंत्री श्री आई.डी. धीमान ने कहा कि सहकारी आन्दोलन से जुड़े सदस्यों को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक जुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उचित दाम पर उपलब्ध करवाई जा रही है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं पर सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का अनुदान उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।

विधायक श्रीमती उर्मिल ठाकुर, पूर्व विधायक श्री के.के. कौशल, कृषि ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष श्री शेर सिंह चौहान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री रसील सिंह मनकोटिया ने सहकारी गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल सोलन जिले के धर्मपुर-स्पाटू मार्ग पर स्थित ध्याड़ी में होटल 'विक्टोरिया कांटीनेंटल इन' का उद्घाटन करते हुए

स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों सोलन ज़िला के धर्मपुर-स्पाटू मार्ग पर स्थित ध्याड़ी में होटल 'विक्टोरिया कॉन्टीनेंटल इन' का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष चार लाख हर्बल पौधों को प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि हर्बल उत्पाद को बढ़ाया जा सके।

उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए पंचकर्म पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जलवायु विविधता है तथा देश की 7.32 प्रतिशत जैव विविधता यहां

धर्मपुर में 'विक्टोरिया कान्टीनेंटल इन' का उद्घाटन

विद्यमान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर सम्भव सहायता उपलब्ध करवा रही है ताकि आर्थिक गतिविधियों का सर्जन कर रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके।

उन्होंने कहा कि गुणात्मक पर्यटन अधोसरंचना के लिए पर्यावरण मित्र पर्यटन परियोजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नए स्थलों का चयन किया जा रहा है। उन्होंने होटल प्रबन्धन को सफलता के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विधायक डा. राजीव सज्जल ने मुख्य मंत्री का स्वागत किया तथा कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डा. राजीव बिन्दल, संसद सदस्य विरेन्द्र कश्यप, विधायक श्री विनोद चन्देल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नरेगा के अंतर्गत 256 करोड़ व्यय

हिमाचल प्रदेश में नरेगा कार्यक्रम के तहत इस वित्त वर्ष में अब तक 256 करोड़ रुपये व्यय कर 132 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के उपरांत दी। इस कार्यशाला का आयोजन प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श के लिए किया गया है।

श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि नरेगा के अंतर्गत 322729 परिवारों को अब तक रोज़गार उपलब्ध करवाया जा चुका है। प्रदेश में जलागम विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाओं में 501577 हेक्टेयर भूमि के उपचार के लिए 515.65 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में 91885 लाख हेक्टेयर भूमि के विकास के लिए 137.82 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी और सुदृढ़ होगी।

कार्यशाला में प्रधान सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डॉ. श्रीकांत बाल्दी और निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज डॉ. आर.एन. बत्ता ने प्रतिभागियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मीडिया आत्म-विश्लेषण कर समाज को सही दिशा दे

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा गत दिनों शिमला के बचत भवन में 'भारतीय मीडिया का बदलता स्वरूप' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के कुलपति श्री विभूति नारायण राय तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय सम्पादक श्री रमेश विनायक थे।

श्री विभूति नारायण राय ने इस अवसर पर कहा कि मीडिया को अपने कार्य का निर्वहन अधिक प्रभावशाली एवं समर्पण से कार्यान्वित करने के लिए स्व नियंत्रण एवं स्व अनुशासन को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गत दो दशकों में समाज के नैतिक मूल्य तेजी से बदले हैं और मूल्यों को बनाए रखने में मीडिया अहम भूमिका निभा सकता है।

श्री राय ने कहा कि कई बार मीडिया द्वारा कुछ मामलों को सनसनीखेज़ बनाया जाता है, जो समूचे समाज के लिए घातक है। मीडिया को समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। समाज के हित में यह आवश्यक है कि मीडिया स्व-निर्धारित आचार संहिता का पालन करे।

उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए 'सेंसरशिप' घातक है और मीडिया को ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए, जिनमें सेंसरशिप लागू करना आवश्यक हो जाए। उन्होंने कहा कि कार्य निर्धारण के स्व-संचालित नियम समय की मांग है और यदि कोई भी व्यक्ति इसकी अवहेलना करता है, तो उसके साथ संस्थान द्वारा सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

श्री राय ने कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में समाचारपत्र उपभोग की वस्तु एवं उत्पाद बन कर रह गये हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मीडिया में व्यापारिक पहलू को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है, तो मीडिया अपनी स्वतन्त्रता को कैसे बनाए रख सकता है।

श्री विभूति नारायण ने कहा कि मीडिया को आत्मविश्लेषण करना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि वह

राष्ट्रीय प्रेस दिवस आयोजित

बल दिया। उन्होंने कहा कि गत दो दशकों में मीडिया में व्यापक बदलाव तथा विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि अनेक बाधाओं के बावजूद हमारा मीडिया संवेदनशील, जागरूक तथा विस्तृत है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई

80 न्यूज़ चैनल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण डॉटा के अनुसार गत 5 वर्षों के दौरान प्रिंट मीडिया की पाठक संख्या में 4 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है तथा गत दो वर्षों में 25 मिलियन नये पाठक जुड़े हैं। 68 मिलियन केबल एवं सेटेलाइट चैनलों के दर्शक हैं और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता देश है।

श्री विनायक ने मीडिया की

शिमला में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर वर्धा अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विभूति नारायण राय तथा हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय सम्पादक श्री रमेश विनायक।

किस दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया को सही दिशा में ले जाने के लिए किसी को आगे आना होगा।

हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक श्री रमेश विनायक ने आत्म-विश्लेषण की आवश्यकता पर

साक्षरता दर के परिणामस्वरुप प्रिंट तथा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के ही विस्तार में सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 70 हजार समाचारपत्र, 53 हजार से अधिक पत्रिकाएं तथा 300 से अधिक टी.वी. चैनल, जिनमें से लगभग

विश्वसनीयता को बनाए रखने पर बल दिया तथा कहा कि मीडिया को समाज के मार्गदर्शक एवं प्रेरणाप्रोत की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता पूर्व पत्रकारिता एक मिशन थी, जो अब व्यवसाय बन गई है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री पी.सी. लोहमी ने कहा कि आधुनिक तकनीक ने समूचे मीडिया में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि मीडिया की विश्वसनीयता में किसी भी प्रकार की कमी समाज के लिए खतरा बन सकती है।

निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क श्री बी.डी. शर्मा ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रेस लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तम्भ है। उन्होंने कहा कि भारत प्रेस परिषद का गठन वर्ष 1966 में प्रेस की स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए ही किया गया था। उन्होंने कहा कि लगभग एक दशक से मीडिया में व्यापक बदलाव आया है, परन्तु इस बदलाव को समाज के व्यापक हित में सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सेमीनार में हुआ विचार-विमर्श सेमीनार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर विचार-विमर्श सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें मीडिया से जुड़े लोगों तथा अन्यों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया।

हिमुडा के उपाध्यक्ष श्री गणेश दत्त, अमर उजाला के संपादकीय प्रभारी श्री गिरिश गुरुरानी, अन्य वरिष्ठ पत्रकार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इससे पूर्व, देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रभाष जोशी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

गिरिराज
हिमाचल की प्रगति और संस्कृति का दर्पण

सबसे बड़ा चिकित्सक तुम्हारा मन है। जब वह नहीं चाहेगा, तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। **–चरक मुनि**

बीजों पर उपदान

प्रदेश सरकार ने राज्य में सूखे से खरीफ की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए किसानों एवं बागबानों को आगामी रबी फसल की बुआई में हर प्रकार के बीज पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस पर सरकार 11 करोड़ रुपये का खर्च करेगी। प्रदेश में रबी फसल में होने वाली बुआई के लिए बीज की कोई कमी न आये इसके लिए सरकार द्वारा पहले ही प्रबन्ध करना सरकार की किसानों के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। इसके लिए सरकार ने प्रबन्ध भी कर लिया है। सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम, नैफेड, हरियाणा बीज निगम तथा अन्य राष्ट्रीय बीज एजेंसियों से इस बाबत बातचीत की है। इसके अलावा प्रदेश के अपने फार्मों में तैयार होने वाले बीज के माध्यम से किसानों एवं बागबानों को इसकी आपूर्ति के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। कृषि विभाग द्वारा रबी की बुआई के लिए लगभग एक लाख क्विंटल बीजों की व्यवस्था कर ली गई है, जिसका वितरण आरम्भ हो चुका है। गेंहू के बीज की 56729 क्विंटल की मांग थी जबकि लगभग 80 हजार क्विंटल बीज की आपूर्ति सुनिश्चित बनाई गई है। इसी प्रकार मटर की 4636 क्विंटल तथा सब्जियों के बीज की 167 क्विंटल की मांग को पूरा किया जा रहा है। हिमाचल जैसे पर्वतीय प्रदेश में कृषि क्षेत्र जोखिम भरा व्यवसाय है। यहां की कृषि ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर करती है। सिंचाई सुविधाएं खेतों के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वर्षा ऋतु को छोड़ वर्ष में नौ माह यहां के खेत बिना पानी रहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि राज्य की वर्तमान सरकार ने किसानों, बागबानों के कल्याण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। वर्तमान सरकार ने जब से सत्ता संभाली है कृषि व्यवस्था में बड़े पैमाने पर विविधता लाने के प्रयास किए हैं। उत्पादन भी बढ़ा है। सब्जी उत्पादन व गैर मौसमी सब्जी तथा फल उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है। किसानों को उन्नत पौध उपलब्ध करवाने के लिए फल पौध नर्सरियों की स्थापना की जा रही है। सत्ता संभालने के पहले दिन से ही कृषकों के हित सरकार के सर्वोपरि रहे हैं तथा उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाये गए हैं। किसान परम्परागत फसल पद्धति की बजाए अब फसल चक्र में विविधता ला रहे हैं। वे अब नई टैक्नोलॉजी अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी उनको सुरक्षा मिली है। हिमाचल प्रदेश में कृषि की स्थिति संतोषजनक और आशा का संचार करने वाली है। इस समय हिमाचल में 90 प्रतिशत से अधिक लोग जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यही उनका मुख्य व्यवसाय भी है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। सब्जी उत्पादन में भी हिमाचल ने नया नाम कमाया है। कृषि क्षेत्र रोजगार का भी एक बड़ा साधन है। इसमें अधिकांश जनता को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होता है। जैसे जैसे सरकार ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जो प्रोत्साहन दिए गए, उसके उत्साहजनक परिणाम सामने आने लगे हैं। युवा वर्ग अब सरकारी नौकरियों के पीछे न भाग कर कृषि को अपना व्यवसाय बनाने लगा है। सरकार के प्रति किसानों का एक विश्वास भी पैदा हुआ है।

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य: एक नजर

●विनोद कुमार सिन्हा

विगत वर्ष जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अवधि साढ़े पांच वर्ष से बढ़ाकर साढ़े छह वर्ष कर दी और इस एक वर्ष की अवधि में छात्रों को अनिवार्य रूप से गांवों में जाकर अपनी चिकित्सा सेवाएं देने की बात की थी तब छात्रों ने बड़ा बवाल मचाया। तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की इस घोषणा का चिकित्सकों ने बड़ा विरोध किया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि विरोध में उतरे चिकित्सकों के तर्क में दम है। बारहवीं कक्षा के बाद चार वर्षों में जब एक इंजीनियर तैयार हो सकता है तो उसके समकक्ष डॉक्टर बनने में अब साढ़े छह वर्ष लगेंगे, ढाई वर्ष ज्यादा। ऐसे में चिकित्सकों की चिंता तो जायज लगेगी ही।

कुछ साल पहले डॉक्टर तब भी चर्चा में थे जब चिकित्सा को केन्द्रीय उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया गया था। उस समय भी बहुत शोर मचा था। चिकित्सकों के इस विरोध पर सर्वोच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी थी कि 'क्या चिकित्सक मरीजों को मारने का लाइसैंस चाहते हैं?'

इसमें संदेह नहीं कि पिछले दो दशक में चिकित्सा तंत्र इतना विशाल और मजबूत हो गया है कि उसके सामने आम आदमी असहाय है। चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी, अस्पताल सरकारी हो या निजी, मरीज और उनके तीमारदारों को बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी भरोसा नहीं रहता कि इलाज ठीक होगा। कभी भरोसे और उम्मीद का पर्याय रही चिकित्सा अब विशुद्ध धंधा बन चुकी है। इस धंधे में दवा निर्माता, विक्रेता, चिकित्सक, पैथालॉजिकल जांच घर, वैज्ञानिक आदि सब मिले हुए हैं। इनकी मिली भगत से चिकित्सा आज दुनिया का महत्वपूर्ण और आकर्षक आमदनी वाला व्यवसाय बन गया है। शहरों में खुलने वाले अस्पताल पांच सितारा होटलों की तर्ज पर सुविधाजनक और आधुनिक बनाये जा रहे हैं। सेवा के नाम पर लगभग मुफ्त में प्राप्त जमीन और सार्वजनिक धन के बदले में खुले इन अस्पतालों में गरीबों को दी जाने वाली कागजी नि:शुल्क सुविधा भी गायब है। आम आदमी बेबस है। वह समझ नहीं पा रहा जिस अस्पताल को वह मंदिर समझता है और चिकित्सकों को भगवान, वे कठोर और धनपिपासु कैसे हो गये?

अब भी देश की 73 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, फिर भी यहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं शहरों के मुकाबले 15 प्रतिशत भी नहीं है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में 2,083 लोगों पर एक चिकित्सक और प्रति 6,000 लोगों पर एक सहायक नर्स उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन 70 से 80 प्रतिशत चिकित्सक और 90 प्रतिशत नर्सें शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत क्या है?

भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए सन् 1946 में बनी डॉ. जोसेफ भोर समिति की सिफारिश थी कि देश में 50 व्यक्तियों पर एक चिकित्सक हो, लेकिन ये सिफारिशें कागजी ही रहीं। कारण कि कोई चिकित्सक शहर से गांव में जाना नहीं चाहता। यहां यह बात ध्यान देने की है कि चिकित्सकों और नर्सों के पद ग्रामीण जरूरतों के आधार पर सृजित किये जाते हैं। चिकित्सकों की नियुक्ति तो गांवों में होती है, लेकिन नियुक्ति के कुछ ही महीने बाद ये डॉक्टर गांव छोड़कर शहर आ जाते हैं।

इसमें संदेह नहीं कि ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुविधाओं का अभाव एक अहम मुद्दा है, लेकिन यह भी सच है कि चकाचौंध के इस दौर में कोई चिकित्सक, अधिकारी या सरकारी बाबू गांव में रहना ही नहीं चाहता। आज भी गांवों में वहां के लोगों के स्वास्थ्य की पहरेदारी वे तथाकथित चिकित्सक ही करते हैं जिन्हें 'झोला छाप डॉक्टर' कहा जाता है।

इस वक्त हमारे देश में डॉक्टर और जनसंख्या का अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के मुताबिक है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की बहुत कमी है। शहरों में जहां 662 की आबादी पर औसतन एक डॉक्टर है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 8,333 की आबादी पर एक डॉक्टर। डॉक्टर गांव की अपेक्षा शहर में काम करना पसंद करते हैं। भोर समिति ने अपने अध्ययन में पाया था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर और जनसंख्या के अनुपात में भारी अंतर है। तब समिति ने अनुशंसा की थी कि ज्यादा से ज्यादा चिकित्सकों को नौकरी देकर गांवों में भेजा जाये।

मगर इस सिफारिश के तीन वर्ष बाद यानी 1975 तक भी स्थिति में बदलाव नहीं आया। इन वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, फिर भी गांवों में चिकित्सकों के पद खाली ही रहे। उदाहरण के लिए 1972 में कुल 5,192 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे। सरकार ने प्रत्येक केन्द्र के लिए दो-तीन चिकित्सकों के पद सृजित किये थे पर मात्र 2,951 केन्द्रों पर ही दो-दो डॉक्टर जा पाए। 2,101 प्राथमिक केन्द्रों पर एक-एक डॉक्टर गया और 140 केन्द्र खाली रहे। उस समय देश में डॉक्टर जनसंख्या का अनुपात 4,200 लोगों पर एक डॉक्टर का था। यह भी तथ्य है कि उसी समय 500 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध था।

चिकित्सकों की संख्या में लगातार वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों के अवसरों से भी चिकित्सकों का 'शहर प्रेम' नहीं डिग पाया। वास्तव में 1960-70 के दशक में बड़ी संख्या में डॉक्टर विदेश चले गये थे। 1963-66 के बीच हुए एक अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि उस दौरान मेडिकल डिग्री प्राप्त छात्रों में 60 प्रतिशत ऐसे थे जिनके माता-पिता या तो सरकारी नौकरी में या स्वयं डॉक्टर थे।

एक अन्य अध्ययन के अनुसार 1978 में 41 प्रतिशत डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे थे। 25 प्रतिशत सरकारी नौकरी और 10.5 प्रतिशत विदेशों में कार्यरत थे। 1990 तक 73 प्रतिशत डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में आ गये थे जबकि सरकारी नौकरी में चिकित्सकों की पर्याप्त मांग थी। उस समय भी यह सुझाव दिया गया था कि डॉक्टर एक निश्चित अवधि के लिए गांवों में जाकर सेवाएं दें लेकिन तब भी इसका डटकर विरोध हुआ था।

ग्रामीण स्वास्थ्य की उपेक्षा की एक वजह मेडिकल शिक्षा की विषय वस्तु भी है, इन दिनों एमबीबीएस शिक्षा का पाठ्यक्रम ही ऐसा है कि वह आम लोगों, खासकर गरीबों से चिकित्सकों का अलगाव बढ़ाता है। मेडिकल शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य यह होना चाहिए कि देश की स्वास्थ्य समस्याओं से निबटने के लिए जरूरी ज्ञान और हुनर चिकित्सकों को दिये जायें। भारत में स्थिति यह है कि पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद मेडिकल छात्रों को देश में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारियों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। उन्हें जिन बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है वे भारत में बहुत कम होती है।

उदाहरण के लिए बहुत से डॉक्टरों को टीबी, कोढ़ या कालाजार जैसे रोगों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। इसके विपरीत विद्यार्थियों को हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, एचआईवी एड्स जैसे रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाता है। सब जानते हैं कि वे बीमारियां उन बहुत थोड़े लोगों को होती हे जो प्राय: शहरी और सम्पन्न वर्ग के होते है। आम बीमारियों की उपेक्षा का कारण शायद यही है कि इनकी चपेट में गरीब लोग आते हैं। शायद यह भी माना जाता हो कि इन बीमारियों का अध्ययन बौद्धिक तौर पर चुनौतीपूर्ण नहीं है।

गरीब मरीजों से चिकित्सा छात्रों के अलगाव का सबसे बड़ा कारण शायद यह है कि चिकित्सा शिक्षा में अस्वस्थता के सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। मेडिकल शिक्षा में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया है कि बीमारी हो जाने पर उसका इलाज कैसे किया जाये। इसमें सामाजिक हालात को समझने की कोशिश नहीं की जाती, यानी यह कि इन बीमारियों का मूल स्रोत क्या है? जो बीमारियां गरीबी या अभाव का नतीजा है उनकी या तो उपेक्षा की जाती है या फिर कुछ समय के लिए कामचलाऊ इलाज कर दिया जाता है। जैसे औरतों में खून की कमी या बच्चों के कुपोषण के मूल कारणों की उपेक्षा की जाती है।

1995 में जारी एक रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'अत्यधिक गरीबी' को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण में एक रोग माना है। इसे जेड 59.5 का नाम दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गरीबी तेजी से बढ़ रही है और इसके कारण विभिन्न देशों और एक ही देश के लोगों के बीच भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इससे स्वास्थ्य समस्याएं और गंभीर हुई हैं। एक आकलन के अनुसार भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रत्येक तीन में से दो बच्चे कुपोषित हैं। गिनती में यह संख्या सात करोड़ से ज्यादा है। विश्व के 17 करोड़ कुपोषित बच्चों से 40 प्रतिशत भारतीय हैं।

मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की मौजूदा नीति साफ तौर पर निजीकरण और वैश्वीकरण की पक्षधर है। सरकार स्वयं स्वास्थ्य क्षेत्र को तेजी से निजी क्षेत्र में धकेल रही है। जाहिर है, सरकार का यह दृष्टिकोण संविधान के संकल्प-सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की भावना के एकदम प्रतिकूल है। शहर-उन्मुखी मौजूदा स्वास्थ्य नीति से डॉक्टर भी प्रभावित हैं और वे मुनाफे के इस धंधे को और विकसित करने में लगे हुए हैं। गांव की परवाह किसे है?

अब तो अस्पतालों के 'शेयर' बाजार में आ रहे हैं। दिल्ली स्थित एक पांच सितारा अस्पताल जनता के 54 करोड़ रुपये और 15 एकड़ जमीन पर इस उद्देश्य से स्थापित होने दिया गया था कि उसमें गरीब रोगियों के लिए तीन सौ बिस्तर और मुफ्त बाह्य रोगी विभाग उपलब्ध होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। दुनिया में अपने किस्म के कुछ चुनिंदा अस्पतालों की श्रेणी का यह अनोखा अस्पताल चिकित्सा सेवा को 'उद्योग' में बदलने का बेहतरीन उदाहरण है।

सवाल केवल डॉक्टरों द्वारा गांव की उपेक्षा का नहीं है। यह हर उस अधिकारी, व्यक्ति और संगठन पर लागू होता है जो गांव और देश के लिए जरूरी है। खासकर उन पर जिन्हें तैयार करने में देश के ग्रामीणों का धन भी लगता है और जिनकी पढ़ाई में गांव के विकास की बात अंतर्निहित है। क्या चिकित्सकों को अपने कर्तव्यों पर जोर देकर मानवता और सेवा को भी अपने काम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए?

साभार-योजना, अक्तूबर 2009

> इसमें संदेह नहीं कि पिछले दो दशक में चिकित्सा तंत्र इतना विशाल और मजबूत हो गया है कि उसके सामने आम आदमी असहाय है। चाहे बीमारी छोटी हो या बड़ी, अस्पताल सरकारी हो या निजी, मरीज और उनके तीमारदारों को बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी भरोसा नहीं रहता कि इलाज ठीक होगा। कभी भरोसे और उम्मीद का पर्याय रही चिकित्सा अब विशुद्ध धंधा बन चुकी है। सेवा के नाम पर लगभग मुफ्त में प्राप्त जमीन और सार्वजनिक धन के बदले में खुले इन अस्पतालों में गरीबों को दी जाने वाली कागजी नि:शुल्क सुविधा भी गायब है। आम आदमी बेबस है। वह समझ नहीं पा रहा जिस अस्पताल को वह मंदिर समझता है और चिकित्सकों को भगवान, वे कठोर और धनपिपासु कैसे हो गये?

कृषक मित्र

गेहूं के साथ मिश्रित खेती करने का उचित समय

दिसम्बर माह के प्रथम पखवाड़े में किये जाने वाले कृषि कार्य

प्रसार शिक्षा निदेशालय, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के कृषि एवं पशुपालन वैज्ञानिकों ने दिसम्बर माह के प्रथम पखवाड़े में किये जाने वाले मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धित कृषि कार्यों के बारे में निम्नलिखित सलाह दी है, जो किसानों के लिए लाभप्रद साबित होगी।

गेहूं

सिंचित क्षेत्रों में या बारानी क्षेत्रों में जहां गेहूं की बुआई न की गई हो तो वर्षा होने पर बारानी क्षेत्रों में या सिंचाई करके सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की पछेती किस्में एच.पी.डब्ल्यू-42 (आराधना), एच.एस.-295, यू.पी.-2338, यू.पी.-2425, राजस्थान-3765 या पी.बी. डब्ल्यू.-373 लगाएं। एक हैक्टेयर के लिए 125 किलोग्राम बीज लगाएं। बुआई केरे में करें। पहले मिश्रित खाद (इफ्को 12:32:16) का केरा और फिर बीज का केरा करें। मिश्रित खाद की मात्रा एक हैक्टेयर के लिए सिंचित क्षेत्रों में 175 किलोग्राम व असिंचित क्षेत्रों में 125 किलोग्राम रखें। जहां गेहूं की बुआई 30-35 दिन पहले की गई हो और खरपतवारों पर 2-3 पत्तियां आ गई हों तो इस अवस्था में गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों का छिड़काव करें। इसके लिए आईसोप्रोटुरॉन (75 प्रतिशत) की 1 कि.ग्रा. व 2, 4-डी की 0.5 कि.ग्रा. मात्रा को 750 लीटर पानी में घोल बनाकर एक हैक्टेयर में चौड़ी व पतली पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए छिड़काव करें।

दलहनी व तिलहनी फसलें

दलहनी एवं तिलहनी फसलों में अगर खरपतवार नियन्त्रण रसायनों का प्रयोग न किया गया हो तो इस समय इन फसलों में निराई-गुड़ाई करें। दलहनों और तिलहनों की गेहूं के साथ मिश्रित खेती भी की जा सकती है।

सब्जी उत्पादन

प्रदेश के निचले एवं मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की तैयार पौध की रोपाई 15-20 सैं.मी. पंक्तियों में तथा 5-7 सैं.मी. पौधों से पौधों की दूरी पर करें। रोपाई के समय 200-250 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 235 कि.ग्रा. इफ्को (12:32:16) मिश्रित खाद प्रति हैक्टेयर खेतों में डालें।

आलू की बीजाई के लिए सुधरी किस्में जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी गिरिराज व कुफरी चन्द्रमुखी इत्यादि का चयन करें। बीजाई के लिए स्वस्थ, रोग रहित साबुत या कटे हुए कन्द (वजन लगभग 30 ग्राम) 2 आंखें प्रति आलू के टुकड़ों में हों, का प्रयोग करें। बीजाई से पहले कन्दों को डाईथेन एम-45 (25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी) के घोल में 20 मिनट तक भिगोने के उपरान्त छाया में सुखाकर बीजाई करें। दवाई का एक बार बनाया हुआ घोल दस बार तक प्रयोग में लाया जा सकता है। आलू की बीजाई अच्छी तरह से तैयार खेत में 15-20 सैं.मी. आलू से आलू तथा 45-60 सैं. मी. पंक्ति से पंक्ति की दूरी पर मेढ़े बनाकर की जा सकती है। बीजाई के समय 200-250 क्विंटल गोबर की गली सड़ी खाद के अतिरिक्त 250 कि.ग्रा. इफ्को (12:32:16) मिश्रण खाद तथा 60 कि.ग्रा. यूरिया प्रति हेक्टेयर खेतों में डालें। आलू में खरपतवार नियन्त्रण के लिए एट्राटॉफ 2.0 कि.ग्रा. या एरिलॉन/ग्रेमीलॉन 1.5 कि.ग्रा. या गोल 0.5 ली. प्रति 750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज अंकुरण से पहले खेतों में छिड़काव करें।

इसके अतिरिक्त खेतों में लगी सभी प्रकार की सब्जियों (फूलगोभी, बन्दगोभी, ब्रॉकली, गांठगोभी, पालक, मेथी, मटर व लहसुन इत्यादि में निराई, गुड़ाई करें तथा नत्रजन (40-50 कि. ग्रा. यूरिया प्रति हैक्टेयर) खेतों में डालें।

फसल संरक्षण:

जिन किसानों ने अभी गेहूं की बीजाई करनी है वे गेहूं के बीज को बैवस्टीन (2.5 प्रति किलोग्राम बीज) से उपचारित करने के बाद गेहूं की बीजाई करें। बीज का उपचार करने से गेहूं की खुली कांगियारी तथा हिल बन्ट आदि रोगों से बचाव होता है। जिन क्षेत्रों में दीमक की समस्या हो वहां पर गेहूं के बीज को क्लोरोपाईरीफॉस 20 ई.सी. (4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज) से उपचारित कर लें या 2 लीटर क्लोरपाईरीफॉस 20 ई.सी. को 25

किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हैक्टेयर बीजाई के समय खेत में डालें।

दलहनी फसलें जैसे कि चना व मसूर में विभिन्न कीट पतंगों की रोकथाम के लिए एण्डोसल्फॉन 35 ई. सी. (2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।

गोभी प्रजाति की सब्जियों की पौध की रोपाई करने से पहले कीटों जैसे कटुआ, सफेद सुण्डी व लाल चींटी आदि की रोकथाम के लिए रोपाई के समय 2 लीटर क्लोरपाईरीफॉस 20 ई. सी को 25 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हैक्टेयर की दर से क्यारियों में डालें। पौध को कमरतोड़ रोग व जड़ गलन रोग से बचाने के लिए इण्डोफिल एम-45 (2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी) और बैवस्टीन (1 ग्राम प्रति लीटर पानी) के घोल से क्यारियों को सींचें। गोभी व अन्य सब्जियों में तेले व पत्ते खाने वाली सुंडियों के नियंत्रण के लिए मैलाथियान नामक दवाई (1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।

पशुधन

सरसों व जई मिश्रित हरा चारे की पहली कटाई आवश्यकतानुसार की जा सकती है। हरा चारा उपलब्ध न हो सकने की अवस्था में पशुओं को जब सूखे किस्म के घटिया चारों पर गुजारा करना पड़ता है तो प्रत्येक पशु को प्रतिदिन शारीरिक भार के अनुसार अधिक से अधिक 50 ग्राम खनिज लवण मिश्रण अवश्य खिलाएं। मिट्टी/धूल जैसा यह पाऊडर कई नामों से बाजार में उपलब्ध हो जाता है। दुधारू पशुओं को सूखे चारों के साथ संतुलित दाना मिश्रण खिलाना और भी जरूरी हो जाता है। सूखे घास पर पलित 10 लीटर देने वाली गाय को 4 किलोग्राम दाना मिश्रण खिलाना आवश्यक है। पशुओं को ठण्ड, विशेषकर ठण्डी हवाओं से बचाने का जरूरी प्रबन्ध करें। पशु के बांधने के स्थान को सुखा रखें। पशुओं को दिन के समय धूप में बांधें।

यदि संभव हो तो चूजों को पुरानी मुर्गियों से 2 सप्ताह तक अलग रखकर पालें ताकि बीमारियों से बचाव हो सके। चूजों के लिए गर्म वातावरण बनाने के लिए और बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए बुखारी इत्यादि का भी अलग से प्रबन्ध करें। ब्रूडिंग के दौरान मुर्गीघर का तापक्रम 70 डिग्री फ. (21 डिग्री सेंटीग्रेड) से कभी भी कम होने पाये और रात दिन के 24 घंटे में से कम से कम 15-16 घंटे प्रकाश कर हर संभव प्रयास करें और उनके दाना मिश्रण में ऊर्जा का मात्रा बढ़ा दें। मछलियों की बिक्री जारी रखें ताकि तालाब अगले साल की तैयारी करने के लिए समय पर खाली किये जा सकें।

किसान भाईयों एवं पशुपालकों से अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र की भौगोलिक तथा पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार अधिक एवं अतिविशिष्ट जानकारी हेतु नजदीक के कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्पर्क बनाए रखें।

निदेशक, प्रसार शिक्षा,
चौधरी सरवण कुमार हि. प्र.
कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर।

रासायनिक खादों का विकल्प गोबर

आज पूरे भारतवर्ष की खेती रासायनिक पदार्थों की वजह से खराब हो रही है। खाद के नाम पर पूरे भारतवर्ष में किसान इन जहरीले रसायनिक पदार्थों का प्रयोग अपने खेतों में करते आये हैं और कर रहे हैं जिनमें डीएपी, 12.32.16, इफ्को, यूरिया इत्यादि है। किसान ज्यादा फसल लेने के चक्कर में इनका ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से भारतवर्ष की बहुत सी खेती योग्य भूमि बंजर होने के कगार पर है। अनुसंधानों से यह साबित हो चुका है कि जहां पर इन रासायनिक पदार्थों का ज्यादा प्रयोग होता है वहां के लोगों को बहुत सी बीमारियां हो रही है जिनमें कैंसर प्रमुख है।

कुछ साल पहले पंजाब व हरियाणा के दो शहरों में एक सर्वेक्षण के द्वारा यह पता चला है कि जहां सबसे ज्यादा डीएपी का प्रयोग हुआ है वहीं पर सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। आज यह बीमारी शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंच गई है और इस बीमारी का कोई न कोई मरीज प्रत्येक गांव में मिल जायेगा। यह सब इन्हीं रासायनिक पदार्थों की मेहरबानी है। आज यदि अपने घर में प्रत्येक खाने पीने की वस्तु को देखे तो मुश्किल से कोई एक ही चीज मिलेगी जिनमे इन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं हुआ है। वैसे भी आज हम इस आधुनिक समय में किसी चीज की गुणवत्ता की बजाय उसकी सुन्दरता की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। इन रासायनिक पदार्थों का प्रभाव गाय के दूध में भी देखने को मिल रहा है। एक पत्रिक में यहां तक पढ़ने को मिला कि जिस मां के दूध को लोग अमृत मानते हैं जोकि नवजात शिशु के लिए बहुत ही लाभदायक है उसमें इन रासायनिक पदार्थों के जहरीले तत्व पाये गये।

अतः हमें इसके दुष्परिणामों को समझना होगा। यदि हम आज नहीं समझे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को कई भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। आज भारतवर्ष का प्रत्येक परिवार इसके कुप्रभाव की वजह से किसी न किसी बीमारी की वजह से पीड़ित है।

यदि हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो गौमूत्र से निर्मित खाद से एक हैक्टेयर भूमि पर धान 30 क्विंटल तक होता था तथा गेहूं 25 से 30 क्विंटल तक होती थी। अब आधुनिक रासायनिक पदार्थों द्वारा निर्मित खाद से मुश्किल से 25 से 27 क्विंटल गेहूं पैदा होती है, यह भी केवल पंजाब और हरियाणा राज्यों में जहां पर ज्यादा से ज्यादा डीएपी डाली जाती है।

अतः हमें समय रहते गौमूत्र की ताकत को पहचानना होगा क्योंकि इसके द्वारा निर्मित खाद लगभग निशुल्क पड़ती है। क्योंकि लगभग किसानों के पशुधन अपने हैं। धरती को जहरीले होने से बचाना है। तो हमें समय रहते गौमाता के मूत्र व गोबर को पहचानना होगा। इसके प्रयोग से खेती की पैदावार बढ़ती जाती है जबकि दूसरी तरफ रासायनिक पदार्थों से पैदावार घटती है। यदि इसका सबको बड़ा उदाहरण देखना है तो हमें अपने जंगलों में देखना चाहिए इसमें न तो डीएपी डाला जाता है और न ही यूरिया फिर भी वनों में बहुत अच्छे व लम्बे वृक्ष हैं।

अतः हमें गौमाता के गोबर व मूत्र से निर्मित खाद, केंचुआ खाद तैयार करके खेतों में डालनी चाहिए क्योंकि केंचुआ ऊपर से नीचे तक जाता है। इसके उलट पुलट से पौधों में बहुत जल्दी विस्तार होता है व नमी की मात्रा भी बहुत दिनों तक रहेगी। यानि जब वर्षा होगी तो वर्षा का पानी जमीन के नीचे तक जायेगा इससे हम बाढ़ आने की समस्या से भी बचेंगे। जबकि दूसरे जहरीले रसायनिक पदार्थों की वजह से जमीन कठोर होती है और जैसे ही वर्षा होती है तो पानी उसमें नीचे तक नहीं जाता। बल्कि गिरते ही नीचे की तरफ बहने लगता है तथा अपने साथ कई गुणा उपजाऊ भाग भी ले जाता है जिसके कारण उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है।

धरती को जहरीले होने से बचाना है तो हमें समय रहते गौमूत्र व गोबर को पहचानना होगा। इसके प्रयोग से खेती की पैदावार बढ़ती जाती है जबकि दूसरी तरफ रासायनिक पदार्थों से पैदावार घटती है।

●अवनित कुमार

लाहौल की नकदी फसल: हॉप्स

प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला बीज आलू व मटर की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहां की वादियों में रोग मुक्त आलू का उत्पादन हो रहा है। मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण आज इस घाटी में सेब का उत्पादन भी किया जा रहा है। घाटी में कृषि बागबानी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। यहां सीवकथार्न की एक परियोजना तथा हॉप्स खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे घाटी के किसानों व बागबानों की आर्थिकी की और सुदृढ़ता मिली।

सबसे पहले हॉप्स की खेती का उल्लेख जर्मनी में 736 ईसा पूर्व मिलता है तथा इसका बीयर उद्योग में उपयोग पहली बार 1079 में किया गया। इंग्लैण्ड में वर्ष 1400 में हॉलैण्ड से हॉप्स को आयात किया गया जबकि 1471 में इंग्लैण्ड में हॉप्स का बीयर उद्योग में उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई। वर्ष 1524 में पहली बार हॉप्स की खेती इंग्लैण्ड में की गई। अमेरिका में इसकी खेती वर्ष 1629 में आरम्भ हुई।

आज हॉप्स का उत्पादन जर्मनी, अमेरिका, चीन, चेक गणराज्य, पोलैण्ड, इंग्लैण्ड, स्पेन, यूक्रेन तथा फ्रांस में किया जाता है। सबसे अधिक उत्पादन जर्मनी में होता है।

लाहौल के निवासी बेमौसमी सब्जी-हरी मटर, बीज आलू तथा हॉप्स की नकदी कृषि से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। संदेह नहीं है कि यह नकदी कृषि फसल यहां के किसानों के लिए आर्थिकी में सहायक है। 'हॉप्स' ह्यूमूलस ल्यूपुलस प्रजाति का एक बेलदार पौधा है जिसके लिए शीत जलवायु के साथ साथ 18 से 20 डिग्री सेलसियस तक तापमान की आवश्यकता है जो लाहौल स्पीति क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त तक उपलब्ध रहती है। भारत में हॉप्स की कृषि मूलतः पहाड़ी क्षेत्रों-जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड में की जाती रही है। पहली बार प्रयोग के तौर पर हॉप्स कृषि 1840 में देहरादून में की गई थी लेकिन वहां इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। लाहौल हॉप्स एण्ड चिकौरी ग्रोअर्स सोसायटी के अनुसार सबसे पहले हिमाचल के ठण्डी थिरोट नामक क्षेत्र में प्रयोगात्मक रूप में इसकी कृषि हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि 1883-1885 के बीच हॉप्स कृषि हिमाचल के लाहौल व पांगी क्षेत्र में प्रयोग के तौर पर की गई थी।

लाहौल स्पीति क्षेत्र में हॉप्स की खेती सफलतापूर्वक की जा रही है तथा यहां सीमांत कृषकों के लिए यह आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। इस क्षेत्र में लगभग 100 हैक्टेयर भूमि पर हॉप्स की कृषि हो रही है। हॉप्स उत्पादन ब्रूअरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण आदान का काम करता है तथा इस उत्पाद को मानकों के आधार पर बनाया जा रहा है। दुनिया के अनेक देशों में इसी कारण से हॉप्स की कृषि की जाती है। 1994-95 में लाहौल घाटी में 120 मीट्रिक टन से अधिक हॉप्स का उत्पादन हुआ था जो 2000-01 तक बढ़कर 275 मीट्रिक टन हो गया। लाहौल घाटी में 70 मीट्रिक टन सूखे हॉप्स तैयार किया जा रहा है।

हॉप्स एक दीर्घकालीन फसल है तथा इसके पौधे 30 से 40 वर्ष तक फल देते हैं। जब हॉप्स के फूल पीले रंग के हो जाते हैं तब उन्हें तोड़ लिया जाता है। तत्पश्चात इन्हें भट्टों पर सुखाने के लिए भेजा जाता है जहां से इसे विधायन के लिए ले जाया जाता है।

हॉप्स एक नकदी उपयोगी फसल है तथा इसके लिए हिमाचल प्रदेश कुछ क्षेत्रों में उपयुक्त जलवायु भी है। हॉप्स कृषि की समन्वित कृषि कार्यक्रम द्वारा इसे विदेशी विनिमय का बहुमूल्य स्रोत के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

❖आर.बी.एल. गर्ग

कृपया
पृष्ठ 6 – 7
के लिए
सेंटरस्प्रेड
देखें

कहानी

अपशगुन

सुबह-सुबह खबर मिली कि निखिल के दादा जी यानि सेठी साहब जोहमारी ही गली में रहते हैं, गुजर गए हैं, तो सुनकर मन खराब हो गया। अभी परसों ही हमारे घर आए थे। पिताजी के पास अक्सर आकर बैठते थे। पिताजी के साथ अच्छा मेलजोल था उनका। रिटायर्ड लोगों की इस नई-नई कॉलोनी में धीरे-धीरे उम्रदराज लोग कम होते जा रहे थे। ज्यादातर अपने पुश्तैनी कस्बों की ओर लौट गये थे। इन अशक्त बूढ़े लोगों के लिए अपने मार्डन बच्चों से निभाना निहायत मुश्किल काम थां

पिछले दस वर्षों से जमाना इतना तेजी से बदला है कि पीढ़ियों के बीच

●जसविंदर शर्मा

बहुत गहरे मतभेदों के साथ तल्ख अनुभवों के जखीरे में कड़वे दुखों का सामान बढ़ता ही गया है। पहले तीसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी में टकराहट होती थी मगर अब तो सूचना क्रांति की अंधी हवा के आगे बाप-बेटे और मां-बेटी तक के विचारों में ध्रुवीकरण होता जा रहा है। सेठी साहब दिल के मरीज थे। पत्नी उनके रिटायरमेंट से काफी पहले एक सड़क दुर्घटना में उनसे बिछुड़ चुकी थी। सेठी साहब ने दोनों लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की। इस मामले में उनकी किस्मत अच्छी रही। कभी कोई कड़वी बात सामने नहीं आई। एक ही बेटा और काफी ठोक बजाकर उसका रिश्ता किया। मगर बहू उन्हें तेज-तर्रार मिली। चलो कड़वी बात तो कोई सहन भी कर ले मगर बहू तो उन्हें इस घर से निकलवाने पर ही तुली बैठी थी। शुरू-शुरू में सेठी साहब ने बहू के साथ पटरी बिठाने की पूरी कोशिश की मगर सब व्यर्थ। हर रात किसी न किसी फिजूल सी बात पर उनकी बहू उन पर बरस ही पड़ती। बेटे ने भी साथ देना छोड़ दिया। इतने बड़े फ्लैट में सेठी साहब को बालकनी कवर करके एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था।

रिटायर हुए तो सेठी साहब अच्छे फिट व्यक्ति थे। सुबह-शाम सैर करते थे, सोसायटी के वेलफेयर के कामों में बहुत रुचि लेते थे तथा दोस्तों की संगति में खुश रहते थे। उनकी बहू ने तो आते ही अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सोसायटी के दफ्तर से जरा सा लेट क्या हो जाते, उन्हें ठण्डा खाना मिलता। कोई यार-दोस्त उनसे मिलने उनके घर आता तो चाय- पानी के लिए कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई जवाब न मिलता। आखिर उन्हें खुद जाकर अपने मित्र के लिए चाय- नाश्ता लाना पड़ता। फिर इस दिल की बीमारी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। एक बार कहीं से पैसों का जुगाड़ करके एंजियोग्राफी करवाई थी उन्होंने, तो डॉक्टरों ने बता दिया था कि उनके दिल में 80 प्रतिशत से ज्यादा नसें ब्लाक हो चुकी है। किसी भी समय दिल का दौरा पड़ सकता है। अब बाई-पास करवा कर ही उनकी उम्र दस-बीस साल बढ़ सकती है।

इतने बड़े ऑपरेशन के लिए उनके बेटे के पास पैसों का जुगाड़ नहीं बन रहा था। लोग तो कहते थे कि निखिल के पापा की जॉब तो अच्छी खासी है। निखिल के दादाजी ने अपने रिटायरमेंट का पैसा मकान बनाने में खर्च कर दिया था। उन्होंने सही सोचा था कि गुजारे लायक पेंशन तो मिल ही रही है। कई जगह से उन्होंने कर्ज पर पैसा लेने की जुगत लगाई मगर बूढ़े व रिटायर्ड आदमी को दो लाख के आसपास कर्जा कौन देता? बेटे से बात होती तो वह उन्हें समझाता कि अब उनकी 70 साल की उम्र में बाई-पास के लिए इतनी चीर-फाड़ करवाना ठीक नहीं रहेगा।

दोपहर तक मुहल्ले के सभी आदमी तथा औरतें सेठी साहब के घर हो आये। हालांकि पड़ोस में ही मौत हुई थी मगर मुझे दफ्तर जाने के लिए श्रीमती ने राजी कर ही लिया था। उसका तर्क मुझे उचित भी लगा था

पिछले दस वर्षों से जमाना इतना तेजी से बदला है। पहले तीसरी पीढ़ी और पहली पीढ़ी में टकराहट होती थी मगर अब तो सूचना क्रांति की अंधी हवा के आगे बाप-बेटे और मां- बेटी तक के विचारों में ध्रुवीकरण होता जा रहा है।

कि घर में वह और पिताजी तो है ही। कोई काम होगा तो वे संभाल लेंगे। मुझे बेकार में अपनी छुट्टी खराब करने की क्या जरूरत है। मेरा दफ्तर पहुंचना था भी जरूरी क्योंकि कैश की चाबियां मेरे पास थीं।

मैं शाम को दफ्तर से जल्दी ही आ गया। मुझे पक्का यकीन था कि शायद सेठी साहब का दाह संस्कार आज ही करें क्योंकि उनकी लड़कियां मुम्बई से आज रात तक ही पहुंच पाएंगी। दफ्तर से आकर मैं सेठी साहब के घर जाने लगा तो पत्नी ने बताया कि सेठी साहब के पार्थिव शरीर को तो शाम चार बजे ही अग्नि दे दी गई थी। यह सब सुनकर बड़ा अचम्भा हुआ और खुद पर शर्म भी आई कि जिस व्यक्ति के साथ पिताजी का इतना उठना- बैठना था और जो हमारी सोसायटी के वेलफेयर के कामों में हर वक्त लगा रहता था, उसकी अंतिम यात्रा में मैं शामिल नहीं हो सका।

रात खाने की मेज पर किस्सा छिड़ गया। पिता जी बोले, 'कैसा जमाना आ गया है। एक ही बेटा है द्वारका प्रसाद सेठी का, और वह कह रहा है कि क्रिया कर्म करने हरिद्वार जायेगा। दफ्तर से छुट्टी नहीं मिल रही उसे। मैं मानता हूं कि उनके बेटे की प्राइवेट नौकरी है मगर मैं पूछता हूं कि क्या बाप रोज-रोज मरता है। ऐसा कौन सा दफ्तर है जहां बेटे को बाप के मरने पर 10-13 दिन की छुट्टी न मिलती हो।' श्रीमती ने भी निखिल की मम्मी की राम कहानी छेड़ दी कि मिसेज सेठी अपने ससुर को बालकनी कवर करके छोटे से बैठ रूम में कैद रखती थी। डॉक्टरों ने तो कहा हुआ था कि मरीज को आंखों से ओझल नहीं होने देना। बस उस अकेले कमरे में न जाने कब सेठी साहब के सीने में दर्द उठा और वे गुजर गये।'

यकायक श्रीमती की आंखों में चमक आ गई। वह बोली, 'पता है, सेठी साहब की अर्थी आज शाम को ही क्यों उठवा दी, क्योंकि कल निखिल का जन्म दिन है न, उस दिन अर्थी उठती तो अपशगुन होता न। अभी तो फटाफट अर्थी को संभालने की अफरा-तफरी मच गई। एक रात रख लेते तो छोटी बेटी भी अपने पिता के अंतिम दर्शन कर लेती। बेटियों को पिता से कितना मोह होता है।' पिताजी तो खाना बीच में ही छोड़कर उठ गये थे। पहले मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं था मगर श्रीमती ने तो जैसे भानुमति का पिटारा ही खोल दिया था। उसने मिसेज सेठी का पूरा लाइफ स्कैच मेरी आंखों के सामने खिंच दिया था। अब मुझे श्रीमती की बातों पर पूरा विश्वास होता जा रहा था।

27 नवम्बर- जन्म दिवस पर

बच्चन जी के प्रति

हिन्दी कविता को जनता तक बच्चन ने पहुंचाया!

कविता थी पहले हिन्दी में घूंघट की सुकुमारी
मुग्ध-मौन-भावकुल-सी थी छायावत-तनधारी,
लज्जा से भी लज्जित होती कोमल पंखों वाली,
'छाया-युग' था छाया का ही पर्दा झिलमिल छाया,
हिन्दी कविता को जनता तक बच्चन ने पहुंचाया!

नये-नये रूप-रंगों में सजकर सरल-सुघड़ बन जाना,
सिखलाया बच्चन ने हिन्दी को हिन्दी बन जाना,
बिना छिपाये कहना अपने सहज मनोभावों को,
सीधा-सरल बोलना हिन्दी के बच्चन से पाया।
हिन्दी कविता को जनता तक बच्चन ने पहुंचाया!

प्यार-जवानी-जीवन की, प्रतीक बनी हाला में,
ले आयी 'मधुकलश' सुबाला जीवन 'मधुशाला' में,
अग्नि-पथ पर भी जीवन के, घूंट 'हलाहल' पीती,
बच्चन की कविता ने जादू सतरंगा दिखलाया,
हिन्दी कविता को बच्चन ने नव पीयूष पिलाया,
हिन्दी कविता को जनता तक बच्चन ने पहुंचाया!

लोकधुनों औ लोकलयों में नयी भंगिमा लायी,
'खेमे-खूंटों' में बच्चन ने धारा नयी बहायी,
'जनगीता' की वाणी से उद्वेलित कर अन्तर को,
कवि बच्चन ने कविता में जीवन का राग सुनाया।
हिन्दी कविता को जनता तक बच्चन ने पहुंचाया!

▸▸प्रो. डॉ. दीनानाथ 'शरण'

लोक-कथाएं प्रभाव छोड़ने में सक्षम

समीक्षा

पुस्तक-	दादी कहो कहानी (लोक कथा संग्रह)
लेखिका-	आशा शैली
प्रकाशक-	विनायक पब्लिकेशन्स इलाहाबाद
पृष्ठ संख्या-	151
मूल्य-	200 रुपये

लोक साहित्य का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि वह व्यक्तियों के बीच से ही उपजता है और इस कारण वह लोकप्रिय भी होता है। वे कहानियां जन- जन के दिलो-दिमाग पर छाई रहती है। उसी साहित्य से वे प्रेरणा लेते हैं जिसे लोक कहकर पुकारा जाता है। वैसे भी मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है, कि अगर उसे कहानियों के माध्यम से कुछ समझाया जाये तो वह निश्चित रूप से उसे प्रभावी ढंग से समझ लेता है। साहित्य रूपी सम्पदा का महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि उसमें जनमानस की सोच, सांस्कृतिक मान्यताएं तथा सामाजिक दायित्वों का अध्ययन करने का सुअवसर प्राप्त होता है। 'नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णो द्यौ समवर्तत। पदभ्यां भूमिदिश: श्रोतातथा लोकां अकल्पयत्।।' उपनिषदों में अयं बहुतौ लोक: कह कर विस्तार को लक्षित किया गया है। लोक शब्द का प्रयोग महाभारत में भी हुआ है और वहां इसे सामान्य जन के अर्थ में ही व्यवहृत किया गया है। :प्रत्यक्षदर्शी लोकांना सर्वदर्शो भवेन्नर:' अर्थात जो व्यक्ति लोक को अपने चक्षुओं से देखता है वही सर्वदर्शी अर्थात उसे पूर्ण रूप से जानने वाला ही कहा जा सकता है। (महाभारत)।

आशा शैली का 'दादी कहो कहानी' लोककथा संग्रह की लोक-कथाएं भी ऐसी हैं जो कहीं न कहीं व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में सक्षम हैं और बेहतर इसलिए भी बन पड़ी है क्योंकि आशा शैली ने बेहद खूबसूरती से इनको शब्दों में पिरोया है।

आशा शैली बहुआयामी व्यक्तित्व है और हर विधा में मेहनत करती है बल्कि यूं कहना ज्यादा सटीक होगा कि जिस विधा में भी कुछ रचती है तो उसमें डूबकर लिखती है और उसे जीती है। यह उसका ऐसा सबल पक्ष है जो उनके अच्छा रचनाकार होने की घोषणा करता है। ये लोककथाएं एवं प्रेरक प्रसंग जीवन के आसपास की घटनाएं हैं। सुखद पक्ष की भी कथाएं हैं। आशा जी को इस कार्य के लिए बधाई देना आवश्यक है।

●सतीश सागर 'सागर'

लोककथाएं बच्चों को संस्कारित करने का काम बेहतर ढंग से कर सकती है। ये सभी लोककथाएं कुछ न कुछ उपदेश अवश्य देती हैं और ये उपदेश थोपे हुए नहीं है और सही तौर पर प्रभाव छोड़ने में सक्षम है।

आशा शैली ने परिश्रम किया है, लोककथाओं को एकत्र करने में और उससे भी महत्वपूर्ण कार्य किया है उनका प्रकाशन करवाकर।

इस संग्रह में भिन्न-भिन्न प्रदेशों की लोककथाएं संग्रहित की गई हैं, यहां तक कि देश की सीमा से बाहर भी आशा शैली की दृष्टि गई है, इसलिए यह संग्रह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही बहुत ही लोककथाएं हिमाचली परिवेश की हैं जिनका देश की मुख्य धारा से जुड़ना बहुत आवश्यक है, जो कि शेष भारत से इस संग्रह के माध्यम से जुड़ जाती है। अंगूठी ने खोला भेद, लड़की और भेड़ का बच्चा, लोकड़ी-लबेलो, करमो की बात, सातवीं लड़की, आदि ऐसी ही हिमाचली लोककथाएं हैं जिन्हें मुख्य धारा से जुड़ना ही चाहिए। इन लोककथाओं के माध्यम से हम हिमाचली जनमानस अर्थात लोक को आसानी से समझ सकते हैं। खा-चिड़ी-उड़-चिड़ी, तुमड़ी, सोने का चूहा, अपनी कमाई, पहचान, बंदरिया रानी, जात्यां के पैर, बुद्धि का करिश्मा, बड़ा दिल किसका, बोल विधाता, ढोल की पोल, हरि इच्छा, राजा और वजीर, ऐसा जनेऊ चाहिए, तू तो निरा शिवा है रे' आदि लोककथाएं प्रभावित करती हैं और व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है। दादी कहो कहानी संग्रह और भी प्रभावी बन सकता था अगर इसमें और लोककथाओं को भी जोड़ा जाता। असल में लोक साहित्य पर जितना कार्य होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है और साहित्यकार सिर्फ एक-दूसरे पर टालने को प्रवृत्ति के शिकार हैं इसलिए काम हो कैसे? मुझे लगता है कि अगर प्रत्येक रचनाकार अपने गांव-गोठ, अपने आसपास बिखरी लोककथाओं को संग्रहित करके प्रस्तुत करे तो शायद हम लोक साहित्य के प्रति सही न्याय कर पायें। सुश्री आशा शैली ने यह कार्य किया है, बड़ी बात है। इस तरह की कुछ पुस्तकें निरंतर आएं तभी हम सही तौर पर लोक को समझ पायेंगे।

इस पुनीत कार्य के लिए हमें इलाहाबाद के प्रकाशकों को भी साधुवाद देना चाहिए जिन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है। आकर्षक रंगीन आवरण, निर्दोष मुद्रण और साफ-सुथरी छपाई वाली यह पुस्तक बड़े काम की है।

क्या आप जानते हैं?

तीसरी दुनिया के देश कौन हैं

तीसरी दुनिया के देश (Third world Countries) उन देशों को कहा जाता है, जो विकासशील राष्ट्र हैं। अधिकांश देश एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमरीका के हैं। इनमें से प्राय: सभी देश पूंजीवादी देशों के उपनिवेश रहे हैं और पराधीनता के काल में इनके संसाधनों का बेहद शोषण हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह देश अपने विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। यह तीसरी दुनिया के देश इसलिए कहलाए जाते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली दुनिया अमरीका तथा इसके साथी और दूसरी दुनिया सोवियत संघ तथा उसके साथियों के प्रभाव से अपने आपको मुक्त रखने का प्रयास करते रहे हैं। भारत, मिस्र, ईरान, चिली आदि देश इसके अंतर्गत आते हैं।

1. विश्व का चन्द्रमा पर भेजा गया वह पहला उपग्रह जिसने सितम्बर 2009 में वहां पानी होने की पुष्टि की?
2. भारत में आई हरित क्रांति के लिए किस अमरीकी कृषि वैज्ञानिक को श्रेय दिया जाता है?
3. वह शहर जहां आठवां प्रवासी भारतीय दिवस (2010) का आयोजन प्रस्तावित है?
4. भारत का वह मुक्केबाज जिसने सितम्बर 2009 में विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीता?
5. 'सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र' कहां स्थित है?
6. हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होती है?
7. भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
8. प्लास्टिक मनीं किसे कहा जाता है?
9. 'गीत गोबिन्द' के रचयिता कौन हैं?
10. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं?
11. चिन्नास्वामी स्टेडियम कहां स्थित है?
12. 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
13. भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन कब समाप्त किया गया?
14. हिमाचल प्रदेश को 18वें पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था?
15. हिमाचल का स्विटजरलैण्ड किसे कहा जाता है?
16. किब्बर गांव किस जिले में स्थित है?
17. हिमाचल प्रदेश में चाय का उत्पादन मुख्यता कहां होता है?

प्रस्तुति-शमा राणा

□□□

उत्तर-1. चन्द्रयान-1, 2. डॉ. नॉरमन बोरलॉग, 3. नई दिल्ली, 4. विजेन्द्र सिंह, 5. श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश), 6. लाल रक्त सैल्स, 7. एच.जे. कानिया, 8. क्रेडिट कार्ड तथा डेबिट कार्ड, 9. जयदेव, 10. डॉ. डुवुरी सुब्बाराव, 11. बेंगलुरु, 12. विजय केलकर, 13. 1858 ई., 14. 25 जनवरी, 1971, 15. खजियार (चम्बा), 16. लाहौल स्पीति, 17. कांगड़ा।

गोदी में जो खिलाया था... वह बदल गया

किसी शायर ने क्या खूब लिखा है:-

बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो,
चार किताबें पढ़कर ये भी, हम जैसे हो जायेंगे।

बचपन कितना खिलंदड़ होता है, मासूम, नाजुक, उच्छृंखल। मुझे अपना शैशव याद हो आता है। कोई फिक्र-फाक्का नहीं। नाचते रहो, कूदते फांदते रहो। मैं दो माह की ग्रीष्मावकाश में गांव चले जाता। आम चूसने का अपना आनन्द था। जो मिला आम खाया, पीया, हजम किया। ढोर-डंगर लेकर चारागाहों में चराने ले जाते। वहां तरह- तरह की खेलें खेलते। गरने इकट्ठे करते। जेबों में भर लेते। छोटे-छोटे घर बनाते। गुड्डे-गुड्डियों के ब्याह रचाते। पूरे मुहल्ले के बच्चे शामिल होते। यहां तक बड़े बूढ़े भी शिरक्त करते। सावन- भादों, बारिश का सुहावना मौसम। आत्मा तक भीग जाये। आनन्द में सराबोर होना सभी के वश की बात कहां? हम नंगे बदन रिमझिम फुहार का आनन्द लेते। अब तो मित्रों आलम यह है-जेहन में पसरा हुआ एक रेगिस्तान है, आजकल बरसात में भीगता कोई नहीं। वर्षा के सुहाने दिनों में मेंढक तालाबों में टर्राते, खेतों में वीर बहूटियां सुर्ख लाल देखने को मिलतीं। जरा सी वर्षा रुकी तो हम चांडाल- चौकड़ी निकल पड़ते। अपने काम की चीजों को एकत्र करने का जनून सवार हो जाता। मुझे केंचुए से भय लगता। मेरा हम उम्र चाचा पवन केंचुये हाथ में पकड़कर मेरे पीछे भागता। धीरे-धीरे मेरा भय दूर भी उसने किया। निक्कर की जेब में पता नहीं क्या-क्या भरा रहता। मां जब कपड़े धोतीं खूब गालियां सुनता। कुएं के पास चले जाते सब। ऊपर से खड्ड का पानी कलकल करता। कुएं में मेंढक टर्राते। उन्हें कुएं से निकालकर उनके पीछे भागना हमारा शगल था।

खड्ड में पानी की कूहल बनाते, छोटा सा घराट तैयार करते। जबलोटा के फल का गरड़ तैयार करते। गरड़ घूमता, फल को कांटों की सहायता से गरड़ का रूप देते। गरड़ गोल-गोल घूमता। चंडाल चौकड़ी प्रसन्न। वहीं बैठकर लोगों के चुराये आमों का रसास्वादन करते। बाबा बसंता और मौसम हरिराम जब चिलम भरने को बुलाते पीछे से हुक्के की नाली से मुंह द्वारा गुड़गुड़ करने का आनन्द पूछो मत। कभी कभी कड़वा जल मुंह में आ जाता। बाबा बसंता की गालियां बड़ी मजेदार लगतीं। उन दिनों सुहागा झूटना भी हमारा शौक बन जाता। बैलों को छड़ी लगती, वे बेचारे सरपट भागते। गति और बढ़ जाती। हम रस्सी को और कसकर पकड़ लेते। कितने-कितने चक्कर लगा लेते। मेरा नाम मुहल्ले वालों ने शहरी बाबू रख दिया था। उनके अथाह प्रेम और स्नेह की क्या बात कहूं? आंखों में पानी भर आता है। कोई भेदभाव नहीं। कोई दूध पिला रहा है तो कोई मक्खन का पेड़ा रोटी पर रखकर दे रहा है। मक्खन वाली लस्सी पीकर अलौकिक आनन्द आ जाता। इतने बढ़िया और सज्जन लोग ढूंढने से नहीं लगे मिलने। अपनी निर्धनता मुफलिसी में रहकर भी प्रसन्न। भाग्य से कोई गिला शिकवा नहीं। नमक मक्की की रोटी पर रखकर लस्सी के छल्ले से पेट भरने वाले लोग। उनके प्रेमाभिव्यक्ति को मैं उनकी बूढ़ी आंखों में आज भी महसूसता हूं। आज न तो बच्चों के पास समय और न ही माता-पिता के पास इतना संयम है। समसामयिक एक शेर सब ब्यां करता है-

डॉ. रजनीकांत

कागज की नींव भी है, खिलौने भी हैं बहुत,
बचपन से फिर भी, हाथ मिलाना मुहाल है।

बड़ों की अपनी दुनिया है। और बच्चे अपने प्रसन्न हैं। पर वह उच्छृंखलता और खिलदंडपन गायब सा लगता है। मां-बाप बच्चों पर बड़े होने का अहसास थोंप रहे हैं। उनका रौशन गायब सा हो रहा है। बचपन लुप्त हो रहा है। रहती कसर केबल, टीवी ने पूरी कर दी है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। प्रौढ़ हो रहे हैं। पढ़ाई का उन पर इतना दबाव है कि वे तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। महंगी शिक्षा ने मां-बाप की कमर तोड़ दी है। मध्यम वर्गीय माता-पिता अपनी हैसियत से अधिक उन्हें कुछ बनाने में लगे रहते हैं। कुढ़ते रहते हैं। बच्चों को ताने मिलते हैं।

वजन पहले तोलिये फिर नापिये बच्चे का कद,
और बस्ते में किताबें कापियां गिन लीजिये।

वे समय से पूर्व ही बड़े बन जाते हैं। इसका अहसास वे समय-समय पर करवाते रहते हैं। माता-पिता को उनके खोने का भय भी लगातार बना रहता है। जब हमारी पहचान ही कोई नहीं तब हमारी पीढ़ी हमसे क्या सीखेगी। क्या संस्कार लेगी? क्या हम उन्हें दे पायेंगे? सावधान होने की जरूरत है। एक शायर के शब्दों में-

वो पलटकर आप पर ही वार न कर दे ये न हो,
इस कदर भी अपने बच्चों को न टोका कीजिये।

हम फरिश्ते न बनकर एक इंसान बने तो कैसा रहेगा? जो हमारे पास है उसे भी खो न दें। बच्चे को बिगाड़ना- बनाना आपके हाथ में है। उसे जैसा भी रूप देना हो आपके हाथ में है। अन्यथा यह न कहना पड़े-

वो शरीक हो गया दंगा फसाद में,
गोदी में जो खिलाया था, बच्चा बदल गया।

बाल कविता

बच्चे

आदमी के अतीत का दर्पण हैं बच्चे,
निश्छलता का सुखद आकर्षण है बच्चे।
निर्लेप, निर्विकार चितचोर व मनमोहक,
मानवीय रूप में ईश्वर के मानिंद हैं बच्चे।
सूनेपन को हरते, बाहों को भरते,
प्यारे मरुस्थल में नदी का नीर हैं बच्चे।
आंखों को सुहाते, मन को भाते,
मां के आंचल का शृंगार हैं बच्चे।
आंखों से सहज सच्चाई झिलमिलाती,
भोर की ताजगी का एहसास हैं बच्चे।
आकाश से गहरे, फूल से खिले-खिले,
धरा पर उल्लास का उत्सव हैं बच्चे।
मेघ से विचरते, अठखेलियां करते,
घर-आंगन का मनोहारी संगीत है बच्चे।
आदेश के अमल को सदैव तत्पर,
गीली मिट्ठी के नरम ढेले हैं बच्चे।
अहंकार से दूर, करूणा के परिचायक,
मानव की मुक्ति का सम्बल है बच्चे।

▶▶डॉ. हिमेन्द्र बाली 'हिम'

स्वस्थ समाज के लिए नशे पर पाबंदी जरूरी

समस्त सृष्टि अमूल्य पदार्थों से भरी पड़ी है। लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कीमती यहां कुछ भी नहीं। जमाने की हर खुशी स्वस्थ लोगों के लिए होती है। रोगी के लिए जीवन अभिशाप बन जाता है। प्रकृति मानव को स्वस्थ अवस्था में पैदा करती है। प्रकृति की इस अलभ्य देन को बनाए रखना ही जीवन का मूल है। स्वस्थ शरीर और शिक्षित आत्मा के बल पर ही किसी राष्ट्र का विकास संभव है। रोगी व्यक्ति सांसारिक कार्यों को करने में अशक्त तथा असमर्थ तो होता ही है, साथ ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी बोझ तथा चिंता का विषय बन जाता है। वैज्ञानिक रीति से अब यह स्पष्ट हो गया है कि नशा कोई भी हो इससे मानव बुद्धि, शरीर और आत्मा का नाश हो जाता है। शराब, भांग, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, तम्बाकू जैसे भयानक नशीले पदार्थ विषतुल्य प्रमाणित हो चुके हैं।

धूम्रपान को ही लें। इसका व्यापक प्रचार हमारे यहां अकबर के राज्यकाल से हुआ माना जाता है। तम्बाकू के चौड़े-चौड़े पत्तों का विभिन्न तरीकों से सेवन किया जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि पशु भी तम्बाकू के विषैले गुणों से परिचित है। ये कदापि इसके पत्ते नहीं चरते। लेकिन प्राणी जगत में अपने आपको सर्वश्रेष्ठ कहलाने वाला मानव इन पत्तों का अलग-अलग रूपों में सेवन करता है। जैसे चिलम अथवा बीड़ी-सिगरेट में भरकर, नसवार बनाकर, पान आदि में रखकर। लेकिन प्रकृति को देखिये वह इन तरीकों पर खुश नजर नहीं आती। धूम्रपान करने वाला जिस धुएं को अंदर ले जाता है वह अंदर भले ही नहीं रह पाता तब भी उसके कारण सूक्ष्म नलियां और ज्ञान तंतु नष्ट हो जाते हैं। इससे पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है।

चिकित्सक तम्बाकू सेवन के कई दुष्परिणाम बताते हैं। कार्बन बनती है जो कलेजे और गले की नालियों में जम जाती है। अमोनिया बनता है जो कुछ समय बाद जिह्वा को फाड़ डालता है। कार्बोनिक एसिड तैयार होता है जिससे सिर दर्द और अनिद्रा रोग लगते हैं। निकोटिन प्रवाहित होती है। यह एक तीव्र विष है जिसकी एक बूंद खरगोश के प्राण ले लेती है। डॉक्टर ब्रोडे ने सबसे पहले इसकी एक बूंद बिल्ली की जीभ पर डाली थी और वह पांच मिनट बाद मर गई थी।

●मोहित

धूम्रपान के अतिरिक्त शराब एक ऐसा नशा है जो आज हमारे राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। मानव दिन भर की खून पसीने की कमाई को शराब में खर्च कर बेताज बादशाह बन जाता है। शराब पीने वाला आरम्भ में अपने पैसे से पीता है लेकिन खर्च बढ़ जाने पर वह अन्य तरीके अपनाता है।

शराब के सेवन से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रयोग के तौर पर गणित के एक छात्र को लगातार पांच दिनों तक शराब पिलाई गई तो पाया गया कि गणित के जिस प्रश्न को वह पांच मिनट में हल कर लेता था उसे करने में उसे 5.38 मिनट का समय लगा।

अफीम को ही लें। जब चिकित्सा विज्ञान ने निश्चेतन दवाओं का आविष्कार नहीं किया था तब यह शल्य क्रिया के दौरान खिलाई जाती थी। आज के युग में यह आनन्द प्राप्ति के लिए खाई जाती है।

गांजा दूसरे पदार्थों की अपेक्षा अधिक विषाक्त मादक पदार्थ हैं। गांजा पीने पर चार पांच कशों के बाद सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। इसका धुआं फेफड़ों को हानि पहुंचाता है।

कोकीन नामक पदार्थ हमारे यहां पश्चिमी सभ्यता की देन है। यह पेरू नामक वृक्ष से निकलती है। इसका परिणाम कम भयानक नहीं। पान में पीपरीन नामक विष होता है। इसमें प्रयुक्त सुपारी में आरकेडाहन और आरकोलीन नामक विष होते हैं। पान का चूना मुंह और पेट की झिल्ली में घुस जाता है। कत्था संकोचन पदार्थ है। यह पेट, मुंह और आंतों को सूखा डालता है। इसके प्रयोग से जिह्वा और मुंह के अंदर स्वाद को ग्रहण करने वाले दाने नष्ट हो जाते हैं।

चाय ने भी अपने चंगुल में समाज के हर वर्ग को बुरी तरह जकड़ा हुआ है। बताते हैं कि 1664 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने लगभग एक किलो ग्राम चाय इंग्लैण्ड के तत्कालीन बादशाह चार्ल्स को भेंट की थी। उनकी रानी केथेराइन को यह बहुत पंसद आई। देखते ही देखते अगले दो वर्षों में समूचे इंग्लैण्ड में इसका प्रसार हो गया। एक स्वस्थ नागरिक ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इस दृष्टि से दिनों दिन बढ़ते नशे के प्रचलन को राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जा सकता है। नशे के क्रूर पंजों में जकड़े मनुष्य राष्ट्र को उत्थान की अपेक्षा पतन की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोगों के कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को अथाह सम्पत्ति व्यय करनी पड़ती है। नशा मुक्त समाज में ही लोगों का जीवन स्तर उन्नत एवं स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।

गृह वाटिका बनाएं पौष्टिकता घर में पाएं

आज हम जिस रफ्तार से 21वीं सदी की ओर बढ़े हैं उतनी ही तेजी से जनसंख्या भी बढ़ी है। फलस्वरूप शहरों व गांवों में खेती योग्य भूमि घटती जा रही है। घटता हुआ जल स्तर व घटती हुई भूमि के कारण आजकल बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं जोकि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। मनुष्य के आहार में सब्जियों का बहुत महत्व है। भोजन में पाये जाने वाले प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज तत्व शारीरिक, मानसिक विकास व शरीर की संरचना के लिए आवश्यक है। यह सभी अवयव सब्जियों से प्राप्त होते हैं। हमारे यहां सभी प्रकार की सब्जियां जैसे जड़ वाली, पत्ते वाली, कंद वाली, फूल, फल एवं फली वाली उगाई जाती है। हर सब्जी का उपयुक्त भाग ही भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन सब्जियों के बढ़ते दाम, बदलते मौसम के मद्देनजर कृषि की नवीनतम तकनीक अपनाकर इन सब्जियों को गमलों एवं गृह वाटिका में उगाया जा सकता है। इससे जहां ताजी व पौष्टिक सब्जियां प्राप्त कर अर्थोपार्जन का साधन बनेगी वहीं खाली समय तथा घर आंगन की जगह का सदुपयोग भी हो सकेगा।

स्थान का चुनाव

घर के आसपास की जगह, दीवार के किनारे जो खाली जगह हो, या कोई भूखण्ड खाली पड़ा हो तो उसका सदुपयोग भी गृह वाटिका के लिए किया जा सकता है। एक छोटे परिवार के लिए 15 मीटर लम्बी व 10 मीटर चौड़ी भूमि पर गृह वाटिका बनाकर साल भर ताजी सब्जियां प्राप्त की जा सकती हैं।

गृह वाटिका से ताजी सब्जियां व स्वस्थ वातावरण प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:-

-जिस क्षेत्र में गृह वाटिका लगानी हो वहां की मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए। यदि भूमि रेतीली या हल्की हो तो काली चिकनी मिट्टी मिला दें। यदि चिकनी है तो उसमें हल्की मिट्टी मिला दें ताकि जलधारण क्षमता बढ़ जाये। कंकड़-पत्थर, घास-फूस व अनावश्यक सामग्री हटाकर लगभग 15 सेंटीमीटर गहरी खुदाई करके कम्पोस्ट खाद मिलाकर भूमि समतल करनी चाहिए।

-उन्नत किस्मों का बीज लगाएं। पत्तेदार सब्जियां गृह वाटिका में अवश्य लगायें।

-गृह वाटिका में बाड़ का प्रयोग बेल वाली सब्जियों को चढ़ाने के लिए प्रयोग करें। इस बाड़ पर लौकी, कद्दू, सेम तोरी आदि के लिए प्रयोग करें।

-जिन सब्जियों की पौध तैयार करनी होती है उनके लिए नर्सरी तैयार करें। आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं निराई करते रहें।

-गृह वाटिका में छोटी-छोटी क्यारियां बनाकर सब्जियों की बीजाई करें। जड़ वाली सब्जियों को मेड़ों पर मूली, आलू, शलजम आदि की बुवाई करें।

-अधिक बढ़ने वाली सब्जियां व पपीता, नींबू, केले आदि को उत्तर पश्चिम की दिशा में लगायें।

-गृह वाटिका की सिंचाई के लिए रसोई घर, स्नान घर आदि का जल प्रयोग करें।

-गृह वाटिका में कीट नियंत्रण के लिए जहरीली दवाइयों का प्रयोग कम से कम करें। यदि दवाई छिड़कानी पड़े तो लगभग एक सप्ताह तक सब्जी न तोड़ें।

-अगर एक ही प्रकार की सब्जी लगानी है तो एक सप्ताह के अंतराल पर बीजें ताकि ज्यादा समय तक सब्जी मिलती रहे।

-फसल चक्र सिद्धांत को अपनायें।

-बुवाई की वार्षिक योजना बना लें। तदानुसार अगेती, मध्य तथा पछेती प्रजातियों की फसलों को उगाएं।

-गृह वाटिका में फूल व तुलसी भी उगा सकते हैं। क्योंकि तुलसी की सुगंधित वायु जहां जहां जाती है वहां का वातावरण शुद्ध बनाती है। यह पौधा मनुष्य के लिए हर प्रकार से उपयोगी है।

अत: गृह वाटिका में हर प्रकार की सब्जियां व फल उगाने से ताजी सब्जियां व पूजा के लिए पुष्प मिलने के साथ-साथ परिवार के लिए व्यायाम, मनोरंजन का साधन एवं समय का सदुपयोग कर सकते हैं।

–सत्य भामा
–डॉ. सुमति रेखा मल्होत्रा

पहाड़ी भाषा कनै साहित्य लोक मंच

लेख

सोच

सोच कई किस्मा दी तुंदी। माह्णू हर बेले कुछ न कुछ सोचदा रैंदा, कदी अपणीया जिंदड़िया दे बारे च, कदी अपणे टब्बरे, न्याणे दे बारे च, कदी अपणे घर-बारे दे बारे च। गलाणे दा मतबल ऐ कि सब कुछ अपणे ई बारे च सोचदा रैया कणे सोचदा रैंदा... कदी अपणे देसे दे बारे च सोचया...? कदी अपणे पर्यावरण दे बारे च सोचया तांई तां जित्थु दिल कित्ता गंदगी सुटदा रैया, तालू दिल कित्ता रुखां जो बड़दा रैया। अज अहां दे आले दुआले इतनी गंदी फैली चुकियो कि हुण साह लैणा बी ओखा ओआदा। मौसम दी मार इत्थु हर माह्णू झेला दा। अगर इस बारे च पैहले सोचया उंदा ता अज शिमला दी आबोहवा वी साफ-सुथरी उंदी।

अपणे देस-परदेस जो साफ-सुथरा रखणा सिर्फ इक किल्ले माहणू दा फर्ज नी ऐ, बल्कि हर माहणू इत्थु घुमणा-फिरणा औंदे। तां क्या दिक्खदे? इत्थु जगह-जगह गंदगिया दे ढेर, जित्थु खाणा उत्थु सुटणा। ऐ सब दिक्खी ने परोणे नाक-मुंह तां सिकोड़दे। सोचदे उंगे इत्थु दे लोक कितणे गंदे हन्, जरा वी खाणे-रैहणे दा सलीका-तरीका नी ऐ। पैहलके सयाणे सैलाणी इत्थु अपणे हिमाचले च औंदे थे तां इत्थु दी खूबसूरतिया दिक्खी ने सुपणेया विच खोई जांदे थे। पहाड़ा च जालू उठदी-वैंदी चिट्टी धुंध हरीया-भरीया-सैलिया पहाड़िया पर औदी थी तां इजां लगदा था कि स्वर्ग ऐं तां बस इसा धरतिया पर ऐं। होरती कुत्थु नी ऐ...। खड्डां, नालुयां च वगदा साफ पाणी अपणे लोकगीतां सांई कितना मिठ्ठा कणे सुरीला लगदा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ां पर चीला दे, चिनारां दे बड्डे-बड्डे रुख छतरिया ताणी करी हर औंदे-जांदे माहणूये दा स्वागत करदे थे। कितणा सोहणा-सुनक्खा था मेरा हिमाचल।

अज पहाड़ा दी राणी शिमला झुलसा दी। पलैं पलैं जा दी। अज वी इसा जो इंतजार ऐं नर्म नर्म चिट्टी मखमली बर्फा दी चादर ओढ़ने दा। आंखी उस मौसमे दे इन्तजारे च हर बेले रस्ता दिक्खां दीयां अम्बरे दा। जालू मौसम दी पैली वर्फ उसदे जलदे-तपदे तने-मणे जो ठण्डक पूजांगी।

अज के टैमे विच माहणू इतना मतलबी होई चुकया कि सिर्फ अपणे, बस अपणे बारे च ई सोचदा। इत्थु तक कि औणे आली पीढ़िया वास्ते क्या रखया। क्या ओणे आली पीढ़ियां ऐ गर्म हवा खांगिया या बंजर होयादे खेतरां ते झुलसियो अंगारेया सांई मिट्टी खांगिया। सुक्के पहाड़ा च उगियां कंडेया आलिया झाड़िया क्या ठंडिया फुहारां दिगियां। नई ना... अजकले दे हालातां दिकखी ने यऐईं लगदा कि औणे आले टैमे विच असां न्याणेयां वास्ते कुछ वी छड्डी के नी जांदे हन्।

● वंदना राणा

कई बरी लोकां जो गलांदे सुणदी कि 'सब कुछ इत्थु रई जाणा कुछ वी अप्पू कन्नै नी जाणा, खाली हत्थ आयो थे, खाली हत्थे चली जाणा।' बेशक ऐ गल्ल सच्ची ऐ, सार्थक ऐ...। पर देई सोच रखणे आले लोक कदी देया वी सोचण कि ओ संसार जो क्या देई ने जांगे... क्या इत्थु छड्डी के जांगे, कणे क्या लेई करी जांगे? गलाणा बहुत आसान ऐ, पर उस गलाणे दा निभाना बड़ा ओक्खा ऐ।

अज मौसमे दे बदले मिजाज असां जो दस्सा दे हन् कि कुदरत कन्नै मजाक करना कितना भारी पुड़दा। रुखां जो बड़दे रैये, पहाड़ां जो कटदे रेये कैत वास्ते अपणे स्वार्थ वास्ते। ठीक ऐ तरक्की वी हौणा चांईदी, तरक्की दे बारे च सोचणा सबणा दा फर्ज वी ऐ पर अपणी तरक्की बास्ते असां कुस्सी दा घर नी उजाड़ी सकदे। असां अपणी तरक्की वास्ते धरती दी गोद उजाड़ी अज उसा दी पीड़ असां समझा दे। क्या पैहले कुदरत दी पुकार कुन्नी सुनी? नई सुणी। अगर सुणीयो उंदी तां अजे ते पंद्रह-सोलह साल पैहलै असां रुख-बूटे लगाओ उंदे जेड़ अज पंद्रह-सोलहा साले दे न्याणेया सांई गबरू जवान उंदे। कणे यऐ धरती माता असां सारेयां जो आशीष दिंदी कि 'जां तुस्सां दी जिंदगी वी हरी-भरी-फुल्लां वरगी खिलयो रैयै-मैहकदी रैये। पर अफसोस अज आशीर्वाद दी जगह धरती माता शाप देआ दी। देया शाप कि ओहणे आलिया पीढ़िया वी इसते शायद नी वचगियां। अज धरतिया जो छड्डा, लोकां अम्बरे पर वी छींडा पाई दित्तया। मौसमे जो अपणे तरीक्के कणे माहणू लयोदा। जालू वरखा चांईदी तालू वरखा लयौदा। जालू धुप्प चांईदी तालू धुप्प लयोदा। चंद्रमे पर तां हुण लोकां टप्परू बनाने दी सोच राखीयो। हर तरीके कणे हर कोई कुदरत कणे खिलवाड़ करादा। छोट्टै ते लाई ने बड्डे तक हर कोई मौसमे ने खेला दा।

इतने खतरनाक नतीजे असां सामने हन् फिरी वी असां नी जागा दे। आंखी नी खोला दे अपणी हिमाचल सरकार ने कुदरत दे बारे च तां सोचया कि पोलीथिन दे इस्तेमाल पर रोक लगाई तियो। अगर सरकारां सांई सारे माहणू वी पर्यावरण जो बचाणे दे बारे च सोचण तां दुबारा असां दा वातावरण साफ सुथरा कणे साह लेणे जोगा ओई सकदा। सबना दी अपणी-अपणी सोच उंदी ए गल्लं तां ऐ। पर जालू अपणी सोच जन समुदाय कणे जुड़ी जाएं तां ओ सोच बहुत बड्डी कणे खरी उंदी। उसां च सबना दा भला उंदा। अज वेला आई चुकया कि सरकार दी सोच जनता दी वी सोच बनी जाए कणे अपणा प्रदेस इक बरी फिरी हरा भरा खुशहाल बनी जाए।

इतणी बर्फ पौए कि पहाड़ा दी राणी परियां सांई सुंदर लग्गे जिआं इक्क इक्क बूंदां कणे घड़ा भरौदां, उजां ई इक्क इक बूटा असां अज्जे ते लगाणा शुरू करगे तां औणे आले टैमे विच असां दी जिंदगी भी हरी भरी सैलिया डालीयां सांई उंगगी। अगर मेरिया इसा सोचा कणे तुसां सारे सहमत हन्। तुसां वी देया सोचदे तां ओणे आली हर सुबह खुशगवार उंगी। ओणे आला हर दिन खिलया खिलया उंगा, कणे हर शाम उंगी सुहानी। अहां दी सोच ई अहां जो सोहणे सुपणे दिखाई करी यथार्थ दी हरी भरी जमीनां पर लेई ने औंगी देया मेरा विश्वास ऐ। देई मेरी सोच ऐ।

सोचने दी गल्ल ऐ सारी
जित्थु जागगे उत्थु भ्याग,
खुशगवार सोच गर रखगे,
खुशहाल बनगा फिरी समाज।

ग़ज़ल

निक्का

● डॉ. पीयूष गुलेरी

मेरी-तां कविता-ऐ, निक्का।
आम आदमी, बेसक निक्का॥
खबनीं, कैह्जो लोक बोलदे।
मिली-जुली निक्के जो जिक्का॥
निक्का, मसीं:-मसीं:-दा जाया।
काह्लू बड्डा हुंग्गा, निक्का॥
निक्का बोल्लै, मौज होइ-गी।
उमरां तांईं रैह्णा, निक्का॥
घर-घर नूहां दे बरतौयां।
दिक्खी, फिक्का रैह्ंदा निक्का॥
रूप, छलैपा, गुण, ताह्लू-तंई।
जाह्लू तिक्कर मांह्णू निक्का॥
सणैं छुब्बेयां निगली-या-दा॥
बड़-ढिड्ढे जो, दिक्खै, निक्का॥
बड़े-बड़े पुत्तर दूंयां दे।
माउ-बब्बे जो बड्डा, निक्का।
इक-मुठ् होणा देस्से तांईं।
अग्गैं बड्डा, पिच्छैं निक्का॥
नेते-वेत्ते खणा पैयो।
दिक्खी तौर बतौरा निक्का॥
बुरेयां-दैं धाणैं नीं चढ़ना॥
सम्झाअ-क:रदा, मिंजो निक्का॥
बाड़ खेतिया खाणा ल:ग्गगा।
तां दस्सा, क्या क:रगा निक्का॥
सीम-सम्हाली, आपर प्यारा।
अम्मां करदी- निक्का-निक्का॥
हुंकारे तैं, बची-बची नैं।
बणी रेअहे्यां, 'पीयूषा' निक्का॥

सबते बड्डा धन

● रूप सिंह हांडा

सबते बडा धन तां सेजा माना जाओ जुणजा धन खर्च करणे पर कम नहीं हंदा। चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता। भाई-भाई में बटवारा नहीं हंदा। ऐसी धनों का भार नहीं हंदा। देश-परदेश में जुणजा धन हमारे साथ-साथ रोहो। ऐबे बात समझी दी आए लागी हली जे ऐशा धन तो विद्या धन होवो। विद्या धन सबते बडा धन माना जाओ। जेसी आदमी ते पास विद्या धन हला, सेजा आदमी सेठ माना जाओ। बाकी धन विद्या धन रे सामणे कुछ बे नहीं अथी। विद्या धन सभी धनों का राजा असो। विद्या धनो रे साथी बाकी सारे धन तेशे ही आपणे आप आओ जेशे राजे के साथ राजे के बजीर, सेनापति, सिपाही व रेके लोग आओ। सभी लोगों में से जे सबसे बड़े छू आदमी चुने जाओ तो राजा व विद्वान असो। विद्वानों का मतलब जेसी आदमी के पास विद्या धन होवो। राजे का मतलब जेसके पास सब संसारिक पदार्थ होवो। राजे व विद्वानों में से बे जे एक बड़ा माना जाओ तो विद्वान असो, राजा नहीं। राजा जो सिर्फ आपणे देश में पूजा जाओ पर विद्वान पूरे संसारों में पूजा जाओ। राजे का राज तो रेका राजा बे छिनी सको पर विद्वानों की विद्या के लिए कोई बे सीमा नहीं हंदी। विद्वानों की विद्या हावे जेशी सब देशो में फैली जाओ। राजा मरणे के बाद कुछ बे नहीं करी सकता पर विद्वान मरणे के बाद बे आपणे विचारों से लोगों की सेवा करदा रोहो। राज पाठ नष्ट होए जाओ पर विद्वानों के विचार नष्ट नहीं हंदे। इसलिए विद्या धन सबते बड़ा धन असो।

विद्या धन ऐशा धन असो जू बांटणे ते कम नहीं हंदा बल्कि जेतणा बांडी तेतणा बड़दा जाओ। विद्या धन बांडणे से बड़ो पर रेके धन बांटणे से घटी जाओ। ऐशा धन ही तो बड़ा धन माना जाओ। भाई-भाई के बीच या परिवार के रेके लोगों के बीच बाकी धन बडी जाओ पर विद्या धन नहीं बंडदा। जेसके पास होवो तेसी ही मिलो। मरणे के बाद बाकी सारे धन ऐसी मातलोको पर रही जाओ पर विद्या धन आदमी के साथ-साथ जाओ। आगले जन्मों में विद्या धन काम आओ। विद्या धन कभी बे नष्ट नहीं होए सकता। विद्या ही आदमी रा तीसरा नेत्र होवो। बाकी दू नेत्र तो पशु पक्षी में बेहोवो। विद्या धन आदमी का तीसरा नेत्र खुली देय। तीसरा नेत्र खुलणे ते बेहद आनन्द मिलो। ऐसी नेत्रों की सहायता ते ही भगवानों के दर्शण किए जा सको। विद्या धन से जितणी मदद दूसरे की, की जा सको, दूसरे धन से नहीं की जा सकती। बाकी धन आदमी में घमण्ड पैदा करो पर विद्या धन आदमी के अंदर सहनशीलता पैदा करो। विद्या ते ज्ञान, ज्ञान ते ध्यान, ध्यान ते नाम व नाम ते धाम।

विद्या धन ऐशा तो सारी उमरो कमाया जा सको पर विद्यार्थी जीवन ऐसी धनो कमाणे के लिए खास टाइम होवो। ऐसी विद्यार्थी जीवनों में विद्या धन ईमानदारी व तपस्या करके कमाया जाओ। जुणजा आदमी ऐसी जीवनो का फायदा उठाओ सेजा आपणा सारा जीवन सुखी बणाओ। सुने चांदी रे समान विद्या धन बेईमानी व छल कपट से नहीं कमाया जा सकता। विद्या धन तां बिल्कुल साच्ची मेहनत से कमाया जा सको। इसलिए विद्या धन सबसे साच्चा धन असो। सबसे बड़ा धन असो। विद्या धन प्राप्त करणे के लिए आपणे माता-पिता व गुरु की आज्ञा रा पालन करणा पड़ो। नियम ते रहणा पड़ो क्योंकि विद्या धन ठगणे से नहीं मिली सकता। विद्या धन प्राप्त करणे तईं जरूरी असो जे विद्यार्थी आपणा मन बसो में राखणा पड़ो। विद्या धन मनो दे बसो इसलिए मन साफ चेहीं। मनो रे बुरे विचार नहीं चेहीं। आच्छा संग करणे ते ही विचार आच्छे बणो। विचार ही तो विद्या धन असो। विचार आच्छे आचार ते आओ। आचार तप करणे ते आओ। विद्या आदमी पशु ते इन्सान बणाओ। मया का धन तो इन्सान को घमण्ड दिलाओ और इन्सान से पशु बणाओ। विद्या आदमी झूठो से सचाई की तरफ, अंधकार ते प्रकाश की तरफ तथा मौत से अमर होणे री तरफ ले जाओ। विद्या की शक्ति ते सारी हथकड़ियां खुली जाओ। मया के धनों के कारणे आदमी दे हथकड़ियां पड़ी जाओ। विद्या धन मोक्ष प्रदान करो बाकी सारे धन तो नरक की सजा देय। विद्या आदमी का भूषण असो। बड़ा कुल या जाति भूषण नहीं अथी।

विद्या धन तभी मिली सको जबे मनो दे जाति, धन, कुल तथा मया की गांठ नहीं रहदी। मन में जबे तक गांठ रोहो तबे तक विद्या मिलणी तेशी ही मुश्किल होवो जेशा गांठ वाले धागे से कापड़ा सीलणा मुश्किल होवो। बड़े बड़े राजे महाराजे होर राजकुमार जबे विद्यार्थी बणे तो तेनिए आपणे मनो की सारी अक्कड़ छाड़ी देई। मनो से राज घराने की गांठ खुली देई। जेशे श्रीकृष्ण व सुदामा एक समान रोहो थिए। श्री कृष्णे विद्या शीखते वख्तो आपणे सारे ठाठ-बाठ व शक्तियां छाड़ी देई। श्री राम-लक्ष्मण बे गरीब लोगों के समान रोहो थिए। आपणे सारे काम आपणे आप करो थिए। गुरु की आज्ञा का पालन करो थिए।

पर्यावरण बदलाव पर वानिकी समाधान में अंतर क्षेत्रीय समन्वय की आवश्यकता पर बल

मुख्य सचिव श्रीमती आशा स्वरूप ने घटते वन क्षेत्र के प्रभाव को कम करने के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग, प्रभावी वन प्रबन्धन के लिए सुदृढ़ प्रशासकीय व्यवस्था, सकारात्मक आर्थिक प्रोत्साहनों को स्थापित करने तथा गरीबों की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं में सुधार पर बल दिया है। मुख्य सचिव गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा आयोजित 'फॉरेस्टरी सोल्यूशनज- स्ट्रेटेजीज फॉर मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन ऑफ द इम्पैक्टस ऑफ कलाइमेट चेंज इन वेस्टर्न हिमालयाज माउंटेन स्टेटस' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थीं।

मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण बदलाव के सम्भावित प्रभावों से निपटने के लिए हिमालयी क्षेत्र, वन योजना एवं विकास कार्यक्रमों में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपरीत प्रभावों को कम करने के लिए नीति एवं प्रबन्धन कार्ययोजना को अपनाया जाना चाहिए। वन उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति के बीच सुनियोजित संतुलन सुनिश्चित बनाने के लिए नीति की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय वनों के स्थायी प्रबन्धन के माध्यम से व्यावसायिक जैव ऊर्जा, कृषि वानिकी, वन संरक्षण एवं वन संवर्द्धन जैसी वनीकरण एवं पुनः वनीकरण परियोजनाएं तथा वानिकी क्षेत्र में हो रहे नुकसान और उन्हें कम करने एवं अपनाने की सम्भावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय प्रारूपकारों को ऐसे उपायों को सुनिश्चित बनाना होगा जिससे विकास की परिधि में पर्यावरण के हित भी बरकरार रहें। उन्होंने कहा कि वानिकी विशेषज्ञों को और अधिक सक्रिय सम्बद्धता से इस क्षेत्र में अधिक लाभ सुनिश्चित होगा।

श्रीमती स्वरूप ने कहा कि पर्यावरण बदलाव का फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बदलाव एवं समुद्र स्तर के बढ़ने से पारिस्थितिकीय उत्पादकता एवं जैव विविधता में बदलाव आएगा तथा कुछ लुप्त होती प्रजातियों के पूरी तरह समाप्त होने का खतरा बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रभावों के कारण होने वाले क्षेत्रीय बदलावों को सामने लाने पर कार्य अभी चल रहा है किन्तु यह तय है कि उष्णकटिबन्धिय क्षेत्रों में पर्यावरण बदलाव के परिणाम और अधिक गम्भीर होंगे। उन्होंने कहा कि विकासशील विश्व की जनसंख्या को इससे खतरा अधिक है क्योंकि इसकी अधोसरंचना इसके प्रभावों से निपटने के लिए उतनी मज़बूत नहीं है। उन्होंने कहा कि बड़ी जनसंख्या का जीवन यापन कृषि, वाणिकी एवं मत्स्य जैसे पर्यावरण संवेदी आर्थिक क्षेत्र पर निर्भर करता है तथा भारत में इसके प्रभावों के अध्ययन से अनुमान लगाया जा सकता है कि पर्यावरण प्रणाली में प्रक्रिया पर सीमित आंकलन के दृष्टिगत अधिक अनिश्चितता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन श्री अवय शुक्ला ने कहा कि वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी नितांत आवश्यक है। प्रदेश सरकार की भावी नीतियों एवं कार्यक्रमों में वानिकी को शामिल किया जाना जरूरी है क्योंकि मौसम में बदलाव से ये सबसे अधिक प्रभावित होगी। उन्होंने वनों पर पर्यावरण बदलाव के प्रभावों की तुलना एवं विश्लेषण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं विख्यात पर्यावरणविद डा. एन. एच. रविन्द्र नाथ ने 'पर्यावरण बदलाव तथा वन, उत्सर्जन, अवशमन, प्रभाव एवं असुरक्षा' पर अपनी प्रस्तुती दी। पर्यावरण सुरक्षा कोष, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख विज्ञानी डा. स्टीवन हैम्बर्ग ने 'लो-सी इकोनॉमी में वनों एवं जैव ऊर्जा की भूमिका' पर अपने विचार व्यक्त किए। केलिफोर्निया विश्वविद्यालय की लॉरेंस बर्कलेय राष्ट्रीय प्रयोगशाला के डा. जयन्त साथैयी ने 'ग्लोबल आर.ई.डी.डी. कार्यक्रम एवं चुनौतियां' पर अपने विचार व्यक्त किए। इन सभी वक्ताओं द्वारा दिए गए व्याख्यानों पर प्रतिभागियों ने प्रश्न भी पूछे।

कम मूल्य पर उपलब्ध होंगे गंदम आटा व चावल

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री सी.पालरासु ने कहा कि उपभोक्ताओं को खुले बाज़ार से कम मूल्य पर गंदम आटा व चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध करवाये जा रहे खाद्यान्नों के अतिरिक्त उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध करवाए जाएंगे।

श्री पालरासु ने यह जानकारी गत दिनों शिमला में विभाग के ज़िला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के दौरान दी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नई नीति के अन्तर्गत सभी श्रेणियों के राशनकार्ड धारकों को आटा 10 किलोग्राम की थैली 145 रुपये में तथा 5 किलोग्राम चावल 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से केवल गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उक्त खाद्यान्न पात्र राशन कार्ड धारकों को ही उपलब्ध करवाए जाएं तथा खुले बाज़ार में इन खाद्यान्नों का दुरुपयोग न हो।

मुख्य मंत्री का इजराइल दौरा

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल इजराइल के उप विदेश मंत्री डेनियल आयलॉन के साथ एक भेंट के दौरान

(पृष्ठ एक का शेष)

प्रो. धूमल ने व्यवस्था से प्रभावित गुणात्मक कृषि उत्पादन एवं किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगी। उन्होंने कहा कि इज़राजल का यह प्रयोग यदि कम उंचाई वाले क्षेत्रों में सेब के उत्पादन में सफल होता है तो हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होंगे।

इजराइल के उपविदेश मंत्री से भेंट

मुख्य मंत्री ने तेलअवीव में इजराइल के उप विदेश मंत्री श्री डेनियल आयलॉन से भेंट कर राज्य तथा राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

इजराइल के उप विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल तथा भारत के मध्य बेहतर मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग कायम है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश मेहमान नवाज़ी के लिए जाना जाता है तथा जब भी इजराइल का प्रतिनिधिमण्डल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आया है उन्हें यहां के लोगों एवं सरकार से समुचित मान-सम्मान मिला है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हिमाचल प्रदेश गए तीन इजराइली नागरिकों के लापता होने की सूचना है। उन्होंने मुख्य मंत्री से आग्रह किया कि उनके बारे में शीघ्र पता लगाया जाए। उन्होंने इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्य मंत्री का आभार व्यक्त किया।

इजराइली उप विदेश मंत्री ने इस अवसर पर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि दोनों देश मानवीय मूल्यों को श्रेष्ठ मानते हैं और दोनों देशों के लोग शांतिप्रिय हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास में गहरी रूची ली।

उन्होंने हिमाचल तथा इजराइल के मध्य आर्थिक सहयोग, विशेषकर टपक तथा फुव्वारा सिंचाई, जल पुनःचक्रण और जल शुद्धिकरण के विषय में आपसी सहयोग का आग्रह किया, जो राज्य के किसानों की सामाजिक-आर्थिक दशा सुधारने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 85 प्रतिशत से अधिक किसान छोटे एवं सीमांत हैं और प्रदेश के लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा जल पर आश्रित है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक समय की मांग है।

मुख्य मंत्री ने श्री डैनियम आयलॉन को विशेषकर कुल्लू दशहरे, जोकि एक अंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य महोत्सव है, के दौरान हिमाचल प्रदेश आने का न्योता भी दिया। उन्होंने इस महोत्सव के लिए इजराइली सांस्कृतिक दल को प्रायोजित करने का आग्रह भी किया।

कृषि एवं व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने पर बातचीत

मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों इज़राइल में वहां के उद्योग, व्यापार और श्रम मंत्री बिनयामिन बैन-इलाइज़र के साथ बैठक की, जिसमें व्यापार, कृषि और जल तकनीक के मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। बैठक में इज़राइल में भारत के राजदूत नवतेज सरना भी उपस्थित थे। इज़राइली मंत्री ने मुख्य मंत्री को जल तकनीक, प्रबन्धन और जल पुनःचक्रण के संबंध में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि इज़राइल में 90 प्रतिशत जल पुनःचक्रित किया जा रहा है और इसमें से 77 प्रतिशत जल का उपयोग सिंचाई कार्यों के लिए किया जा रहा है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने इज़राइली मंत्री से आग्रह किया कि वे जल पुनःचक्रण से संबंधित तकनीकी हस्तांतरण में हिमाचल प्रदेश का सहयोग करें, ताकि प्रदेश के किसान भी इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि राज्य में 353 करोड़ रुपये की महत्त्वाकांक्षी पंडित दीन दयाल किसान बागबान समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है, जो किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही है और तकनीक हस्तांतरण राज्य सरकार के प्रयासों को और बल प्रदान करेगा।

प्रो. धूमल ने इस अवसर पर मौसम में आ रहे बदलाव से होने वाली चुनौतियों से निपटने विशेषकर जो किसानों की आर्थिकी पर प्रभाव डाल रही हैं, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी इज़राइली मंत्री को दी।

इज़राइली मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में हो रहे विकास में गहरी रुचि ली।

इससे पूर्व, मुख्य मंत्री ने प्रदर्शनी स्थल का दौरा किया और वहां नानदान जैन बूथ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इज़राइल में भारतीय दूतावास द्वारा एक प्रस्तुतिकरण दिया गया।

राज्य में खेल अकादमी खोलने का आग्रह

सांसद, श्री अनुराग ठाकुर ने श्री दलीप सिंह राणा 'ग्रेट खली' से आग्रह किया है कि वे हिमाचल प्रदेश में खेल अकादमी आरम्भ करें ताकि प्रदेश के योग्य खिलाड़ियों को विभिन्न खेल गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जा सके। यह आग्रह उन्होंने गत सायं 'खली' के साथ हुई बैठक में किया। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ग्रेट खली ने खेल क्षेत्र में अपना नाम अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है तथा वे नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

श्री ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं ने कहा कि वे राज्य सरकार से ग्रेट खली को हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेस्डर बनाने का मामला प्रदेश हित में उठाएंगे, जो राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश को प्रोत्साहित करेगा।

मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना...

(पृष्ठ एक का शेष) उत्पादन में 26 प्रतिशत की वृद्धि तथा सब्जी उत्पादन में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिकी में भारी बदलाव आया है। इसके साथ-साथ पारम्परिक फसलों में भी 6 प्रतिशत तथा फल उत्पादन में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत कार्यान्वित किए जा रहे वृहद पौधरोपण अभियान के कारण 8,119 हेक्टेयर क्षेत्र को वन क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भू-संरक्षण के लिए 3,67,681 ब्रश वुड चैक डेम, 71, 944 पत्थरों के ढांचे और 62,074 तारों के ढांचे तैयार किए गए जिससे किसानों की उपजाऊ भूमि का संरक्षण सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने कहा कि परियोजना आरम्भ होने के उपरान्त गत वर्षों में 704 किलोमीटर पैदल चलने योग्य रास्ता, 268 छोटे पुलों का निर्माण किया गया जिससे 2,658 गांवों के 3,15,961 लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रो. धूमल ने कहा कि पेयजल सुविधाओं के सुधार तथा पेयजल समस्या से ग्रसित गांवों में 281नए जल स्त्रोत तैयार किए गए तथा 583 पुराने जल स्त्रोतों की मरम्मत की गई जिससे 45,700 परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि हरित क्षेत्र बढ़ाने से पशुपालन को प्रोत्साहन मिला है तथा गाय के दुग्ध उत्पादन में 11 प्रतिशत व भैंस के दुग्ध उत्पादन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित क्षेत्रों में परियोजना की गतिविधियों की निगरानी के लिए 1,872 स्वयं सहायता समूह, 298 यूजर्ज ग्रूप्स एवं 532 कॉमन इन्ट्रस्ट समूहों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण आर्थिकी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाने में वरदान सिद्ध हो रही है। टास्क टीम लीडर श्री नॉरमन पिकानी ने परियोजना के अच्छे परिणाम हासिल होने पर मुख्य मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि जल प्रबन्धन गतिविधियों को पूरे विश्व में और प्रभावी सहायक टास्क लीडर श्री रंजन सामन्तरा ने कहा कि विश्व बैंक हिमाचल प्रदेश को कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने सम्बन्धी जरूरतों पर ध्यान देगा। उन्होंने अधिकारियों को विश्व बैंक की स्वीकृति हेतु एक परियोजना भेजने की सलाह दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अवय शुक्ला, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री भीम सेन और विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी श्री सौरज़िन ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे।

जैविक उर्वरक उत्पादन में...

(पृष्ठ एक का शेष) प्रो. धूमल ने कहा कि हिमालयी राज्यों में से एक हिमाचल प्रदेश में मौसमी चक्र में बदलाव से पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक बारिश अथवा कम वर्षा होने के कारण प्रदेश की कृषि एवं बागबानी गतिविधियों को व्यापक नुकसान हो सकता है, जिससे प्रदेश की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर लोग कृषि गतिविधियों से जुड़े हैं, ऐसे में कृषि के नुकसान से राज्य की समूची आर्थिक व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश पर्यावरण के प्रति सजग है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक ऐहतियाती पग उठाए गए हैं। प्रदेश में व्यापक तौर पर पौध रोपण अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है तथा स्वयंसेवी संगठनों एवं आम लोगों के सक्रिय सहयोग से देवदार जैसे पौधों को पुनर्जीवित करने के लिए भी अभियान छेड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के समुचित दोहन के लिए स्वच्छ ऊर्जा उत्पादक जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में जलविद्युत को विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है, जिससे जलविद्युत क्षमता का तीव्र दोहन तथा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि राज्य में जल प्रबंधन के लिए अलग से जल प्रबन्धन बोर्ड स्थापित किया गया है तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए प्रभावी पग उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमालय के संरक्षण से वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव को व्यापक तौर पर कम किया जा सकता है। प्रदेश सरकार हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है तथा समूचे विश्व के पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए हिमालय के पर्यावरण संरक्षण के लिए हिमालयी राज्यों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए हर मंच पर उचित मुआवजे की मांग को उठाया गया है।

केन्द्रीय वित्त मंत्री ने महिला साक्षरता के लिए प्रदेश को सराहा

(पृष्ठ एक का शेष) अपनी पाशविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसे स्वार्थ, संकीर्ण मानसिकता और लालच से ऊपर उठकर मानव कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने युवाओं में दक्षता सृजित करने के लिए राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन आरंभ किया है, जो कि उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट पर कार्य करना आरंभ कर दिया है।

केन्द्र सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और शिक्षा विस्तार, उत्कृष्टता एवं बराबरी पर बल दिया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपनायी गयी 11वीं पंचवर्षीय योजना में दृष्टिगोचर होता है, जिसमें शिक्षा के लिए 3 'ट्रिलियन' रुपये की व्यवस्था की गयी है। यह दसवीं योजना से चार गुणा अधिक है। कुल योजना में शिक्षा का हिस्सा 7.7 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा, जो कि सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर सकारात्मक कदम है। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती प्रभा राव ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के कंधों पर राष्ट्र निर्माण की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वस्थ समाज के निर्माण में शिक्षा का विशेष योगदान है।

शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान ने डिग्री तथा मैडल प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन के महत्त्वपूर्ण पड़ाव को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत अब वे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा सभी की आवश्यकता बन गयी है, जिसके बिना व्यक्ति आज के मशीनी एवं भौतिक संसार में असुरक्षित है।

हि.प्र. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सुनील कुमार गुप्ता ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी, कुलाधिपति श्रीमती प्रभा राव और अन्य का आभार व्यक्त किया। विधायक सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, गोविन्द ठाकुर, पूर्व सांसद श्री कृपाल परमार, प्रधान सचिव शिक्षा एवं प्रधान सचिव वित्त भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्य में गैस आधारित पॉवर प्लांट स्थापित करने का अनुरोध

हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 500 मेगावाट क्षमता का गैस आधारित पावर प्लांट स्थापित करने का अनुरोध किया है। राज्य के मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों नई दिल्ली में राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि सर्दियों के दौरान राज्य की विद्युत परियोजनाओं में पानी के स्तर में गिरावट आने से बिजली का उत्पादन गिर जाता है, जिससे राज्य की बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य में हुए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण की वजह से वर्ष 2012 तक सर्दियों में बिजली की मांग तथा आपूर्ति में 800 मैगावाट का अन्तर आ जाएगा, जिसके स्थाई समाधान की उपयुक्त व्यवस्था करने की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को आबंटित 100 मैगावाट बिजली को बढ़ाकर 400 मेगावाट करने का अनुरोध किया ताकि राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं का स्थाई समाधान हो सके।

प्रो. धूमल ने केन्द्र से गैर आर्बंटित कोटा के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 15 अक्तूबर से 15 अप्रैल तक 15 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को नीतिगत तौर पर प्रदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के गैर आबंटित बिजली कोटा की तदर्थ नीति से राज्य को उचित समय पर पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसकी वजह से राज्य सरकार को मजबूरन बिजली कटौती करनी पड़ती है।

उन्होंने बताया कि राज्य में सामूहिक तकनीकी एवं वाणिज्य

मुख्य सचिव द्वारा बेहतर जल प्रबन्धन की आवश्यकता पर बल

नुकसान 15.1 प्रतिशत आंका गया है, जोकि देश भर में न्यूनतम है। उन्होंने बताया कि राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को देश भर में न्यूनतम दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है तथा किसी भी वर्ग को मुफ्त बिजली प्रदान नहीं की जा रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य की चिन्हित 23000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता से अब तक 6500 मेगावाट क्षमता का दोहन किया गया है। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 10 हजार मेगावाट जल विद्युत क्षमता का दोहन किया जाएगा, जो कि राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा कि 12वीं योजना के अंत तक राज्य में 15 हजार मेगवाट क्षमता के दोहन का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य मंत्री ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत मार्च 2010 तक 50 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया जाएगा तथा 2010 के अंत तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में योग्यता मापदण्ड में छूट प्रदान करने, जनसंख्या मापदण्ड में छूट देकर जनसंख्या मापदण्ड को 10,000 से 5,000 तक लाने का अनुरोध किया तथा बताया कि वर्ष 2001 की गणना के दौरान 5,000 जनसंख्या वाले अनेक कस्बे अब 10,000 जनसंख्या का आंकड़ा पार कर गए हैं।

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी हि.प्र. विश्वविद्यालय शिमला में आयोजित दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रा को डिग्री प्रदान करते हुए।

हर सरकारी शिक्षण संस्थान में होगी शौचालय सुविधा

राज्य सरकार सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, विशेषकर सुलभ शौचालय अंतरराष्ट्रीय संस्था की सहायता लेने की संभावनाओं पर विचार करेगी।

यह जानकारी मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने गत दिनों हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान फेयरलांस शिमला में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर दी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि पर्यावरण के प्रदूषित होने में खुले में शौच जाने को सबसे बड़ा कारण माना जाता है और सुरक्षित एवं वैज्ञानिक उपाय अपनाकर इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सुलभ अंतरराष्ट्रीय संस्था खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है।

प्रो. धूमल ने कहा कि नरेगा में ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं। विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में घर-द्वार के समीप रोजगार देने में नरेगा सहायक सिद्ध हुआ है। उन्होंने नरेगा को और अधिक उत्साह के साथ कार्यान्वित करने पर बल दिया। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अधिक से अधिक संख्या में जॉब कार्ड तैयार करें और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लघु तथा सूक्ष्म विकासात्मक योजनाएं तैयार करें जो आधारभूत अधोसंरचना के साथ-साथ लोगों को रोजगार भी दें। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर विकास के लिए प्रदान किया जा रहा एक-एक पैसा लोगों के कल्याण में लगाया जाना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आबंटित हर योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 2009 तक तैयार कर, उसे 15 जनवरी, 2010 तक हर हाल में राज्य सरकार को सौंपें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि नरेगा के कार्यान्वयन में हिमाचल प्रदेश समूचे उत्तर भारत में अग्रणी है। वर्ष 2008-09 में नरेगा के तहत 332 करोड़ रुपये व्यय किए गए जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 480 करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नरेगा के तहत छोटे और सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने की अपार संभावनाएं हैं। जलागम प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को केन्द्र से 138 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2010 तक खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य हासिल करने के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और श्रेष्ठ विद्यालयों को प्रोत्साहन देना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्यशालाओं को वार्षिक स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

प्रधान सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने मुख्य मंत्री का स्वागत किया।

सभी पंचायतों को मिलेगी वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के आग्रह पर हिमाचल प्रदेश के लिए 3.50 करोड़ की उपग्रह संचार परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना के तहत प्रदेश को 1.72 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त भी केंद्र ने जारी कर दी है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली में गत दिनों आयोजित बैठक के उपरांत यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस परियोजना के मंजूर होने से सभी पंचायतों को पहली बार वीडियो काफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। वीडियो काफ्रेंसिंग की सुविधा मिलने के बाद जहां पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को गति मिलेगी वहीं पंचायतें अपनी समस्याएं भी आसानी के साथ सरकार के समक्ष रख सकेंगी।

कण्डाघाट के समीप खुलेगा हिमाचली फूड एण्ड क्राफ्ट केन्द्र

पर्यटन विभाग के एक प्रवक्ता ने गत दिनों शिमला में बताया कि मैसर्स डेस्टिनेशन लिमिटेड ने शिमला-कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर डेस्टिनेशन होटल के समीप हिमाचल फूड एण्ड क्राफ्ट केन्द्र खोलने का प्रस्ताव पर्यटन विभाग के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में प्रधान सचिव पर्यटन श्रीमती मनीषा नंदा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डेस्टिनेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्तावित फूड एण्ड क्राफ्ट केन्द्र में फूड कोर्ट, हस्तशिल्प एवं हथकरघा केन्द्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, शॉपिंग बाजार और जन सुविधाएं होंगी। यह केन्द्र समृद्ध हिमाचली संस्कृति, हस्तशिल्प और कृषि एवं बागबानी उत्पादों को प्रोत्साहित करेगा।

प्रवक्ता ने कहा कि यह केन्द्र राज्य में अपनी तरह का पहला केन्द्र होगा और राज्य के अन्य भागों में भी ऐसे केन्द्र खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। निदेशक पर्यटन, विशेष सचिव पर्यटन और संयुक्त सचिव पर्यटन भी बैठक में उपस्थित थे।

केन्द्र से औद्योगिक पैकेज अवधि बढ़ाने की मांग

हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्र से राज्य के औद्योगिक पैकेज को वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक बढ़ाने की मांग की है।

नई दिल्ली में गत दिनों राज्यों के उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्री किशन कपूर ने कहा कि भारत सरकार की औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा वर्ष 2008 के मध्य में जारी किए गए एस.आई.ए. आंकड़ों के अनुसार अगस्त 1991 से अप्रैल, 2008 तक सारे देश में औद्योगिक निवेश के प्राप्त प्रस्तावों में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी मात्र 0.54 प्रतिशत है, जिससे स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश अपनी क्षमता के अनुरूप दूसरे राज्यों की तुलना में औद्योगिक पूंजी निवेश को आकर्षित नहीं कर पाया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों में अग्रणी होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास में काफी पीछे है।

श्री कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयत्नों एवं केन्द्र सरकार के औद्योगिक मित्र दृष्टिकोण के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा 7 जनवरी, 2003 को प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज की घोषणा से प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को गति मिली है। हिमाचल प्रदेश को इस पैकेज के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं आयकर में निर्धारित अवधि के लिए छूट के साथ-साथ प्लॉट व मशीनरी में पूंजी निवेश पर अनुदान प्रदान किया गया है। इस औद्योगिक पैकेज के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगपतियों से निवेश के काफी प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी, 2003 से सितम्बर, 2009 तक 12,390 औद्योगिक इकाईयों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया, जिनमें कुल 39,667 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्रस्तावित है तथा 4,46,627 लोगों को रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इनमें से अब तक कुल 6058 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश वास्तविक रूप से उद्योगों में हुआ है और 78,179 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों की तुलना यदि हम पैकेज के पहले के आंकड़ों से करें तो उस समय प्रदेश में मात्र 2610 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश था और 1,54,775 लोगों को रोजगार उपलब्ध था। निश्चित रूप से पैकेज के उपरांत प्रदेश में औद्योगिकरण में गति आई है।

एड्स जागरूकता अभियान 1 से 25 दिसम्बर तक

प्रदेश सरकार द्वारा एड्स के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी तरह के एड्स जागरूकता अभियान का शुभारंभ मुख्य मंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल द्वारा एक दिसम्बर, 2009 को एड्स दिवस के अवसर पर किया जाएगा जो 25 दिसम्बर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस तक चलेगा। इसी दिन शिमला के ऐतिहासिक रिज पर रक्त दान शिविर, पुलिस कर्मियों द्वारा रैड-रिबन परेड तथा साइकल करतब भी आयोजित किये जायेंगे। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉ. राजीव बिन्दल ने गत दिनों शिमला में एड्स कंट्रोल सोसायटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। डॉ. बिन्दल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा एड्स से बचाव हेतु कई पग उठाए गए हैं, जिसके तहत एड्स रोगियों के लिए प्रदेश भर में स्थापित आई.सी.टी.सी. सैंटरों को बढ़ाकर 44 कर दिया गया है। एड्स रोगियों के उपचार के लिए चलाए जा रहे ए.आर.टी. सैंटरों की संख्या दो कर दी गयी है। गत वर्ष प्रदेश में 51 हजार महिलाओं व पुरुषों की कांउसलिंग की गयी है। उन्होंने बताया कि दो आई.सी.टी.सी. वैन प्रदेश भर में घूम कर लोगों को एड्स के प्रति जागरुक कर रही है।

प्रो. जे.सी. शर्मा लोक सेवा आयोग के नये सदस्य

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) सी.एम.शर्मा ने गत दिनों शिमला में प्रो. जे.सी. शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनियता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की मुख्य सचिव श्रीमती आशा स्वरूप भी उपस्थित थीं। प्रो. जे.सी. शर्मा का जन्म 14 अक्तूबर, 1952 को कांगड़ा ज़िले के आलमपुर में हुआ। उन्होंने वर्ष 1969 में 10वीं राजकीय उच्च पाठशाला गदेर से, वर्ष 1973 में राजकीय कालेज धर्मशाला से जिऑग्राफी में बी.ए. ऑनर तथा वर्ष 1975 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से एम.ए.किया। प्रो. शर्मा ने पंजाब विश्वविद्यालय से जिऑग्राफी में पीएचडी की डिग्री हासिल की।

प्रो. शर्मा ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जिऑग्राफी विभाग के वर्ष 2002से 2004 तथा 2006 से 2008 तक अध्यक्ष रहे। उनके हिस्से में 39 प्रकाशन भी शामिल हैं।

ids'kd ch-Mh- 'kekZ fun'kd lpuk ,o tu lEidZ foHkkx] fg-iz- f'keyk&171002] eædd jktho dekj 'kdj fu;ksfDr] eæ.k rFkk y[ku lkexh foHkkx] f'keyk&171005] Qksu 2830378] i/kku lEikndh ch-Mh- 'kekZ ofj"B lEikndh vkj-,l- uxh] lEikndh ;knfoUnj flg pkgku] dk;ky; fg-iz- eæ.kky; ifjlj] f'keyk&171005] Qksu o QDl 2633145] b&ey giriraj hp@gmail.com., girirajhp@yahoo.co.in OR girirajweekly 1978@yahoo.co.in iklr LFkku fxfjjkt dk;ky; fxfjjkt lkIrkfgd eæ idkf'kr y[kka ea O;Dr fopkjka ls lEikndh; lgefr vfuok;Z ugha